20 अप्रैल, 2026 ★ वर्ष 35, पृष्ठ संख्या 72, अंक 04

राजस्थान सुजस

विकास की राह पर
ऊर्जावान राजस्थान

राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा

79,459 करोड़ रुपये

मेट्रो फेज-2

13,038 करोड़ रुपये

"प्रदेश में उद्योगों को माल परिवहन एवं निर्यात के लिए जलमार्ग उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।"

- राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है।
- किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं।
- मंदिरों के विकास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता है।
- राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिले, ताकि वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।
- आस्था की सेवा सबसे बड़ी जनसेवा है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राज्य सरकार तीर्थ स्थलों के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है।
- राज्य सरकार बाल विवाह उन्मूलन और बालिका शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पित है।
- राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- आमजन की छोटी से छोटी समस्या का समाधान करना राज्य सरकार का ध्येय है।
- राज्य सरकार ने पहले दिन से ही जनता की सेवा के संकल्प पर कार्य करना शुरू कर दिया था।
- राज्य सरकार प्रदेश के तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए काम कर रही है।
- राज्य सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण सहित विभिन्न कार्यों से पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।
- राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।
- राजस्थान को देश का नंबर एक राज्य बनाना ही राज्य सरकार का संकल्प है
- हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता बनें। ■

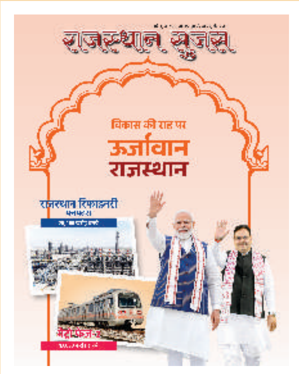

प्रधान संपादक
राकेश शर्मा

वरिष्ठ संपादक
डॉ. गोरधन लाल शर्मा

संपादक
अजय कुमार

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
मोहित जैन

संकलन एवं वितरण
ऋतु शर्मा
रणवीर सिंह कुशवाह

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स
लागत मूल्य 37.00 रुपये

आमंत्रण

'राजस्थान सुजस' पत्रिका के लिए राज्य सरकार की योजनाओं, नवाचार, राजस्थान की संस्कृति व धरोहर आदि विषयों पर आधारित लेख आप editorsujas@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। चयनित लेख सुजस में प्रकाशित किए जाएंगे।

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80581 15790
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 35 अंक 04 अप्रैल, 2026

इस अंक में

सम्पादकीय	04
राजस्थान दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश	05
प्रधानमंत्री की राजस्थान यात्राएं	08
विकसित राजस्थान@2047 ...	15
हरित विकास का आधार ...	20
महिला पुलिस कर्मियों की प्रेरक कहानियां	24
ऑरेंज इकोनॉमी	29
सहकारिता से सुदृढ़ हो रहा भण्डारण तंत्र	32
नारी शक्ति से कृषि सशक्तीकरण...	40
मंगला पशु बीमा योजना	44
तारबंदी योजना	45
सोनी जी की नसियां	46
पाती अपनों को मुहिम	48
जनजाति क्षेत्र की तैराकी प्रतिभाएं	50
धींगा गवर	52
प्रवेशोत्सव-2026	56
राज उन्नति ...	58
From Darkness to Development ...	59
राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2026	60
औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026	62
लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़	64
सामयिकी	65
सुजस प्रश्नोत्तरी	70

राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा **10**

राजस्थान सम्पर्क 181 **36**

गणगौर उत्सव **28**

मन की सुनें जीवन चुनें **54**

सूरज से पैदा हो रही बिजली... **34**

धरोहर **71**

संपादकीय

आधारभूत विकास से जनविश्वास तक

सशक्त होता राजस्थान

"बहुजनहिताय–बहुजनसुखाय" मात्र एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि सुशासन की वह आधारभूत दर्शन–रेखा है, जिसमें प्रत्येक नीति और प्रयास का मूल केंद्र जनहित एवं व्यापक लोककल्याण होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए आधारभूत संरचना के सुदृढ़ विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास, कृषि में नवाचार के संवर्धन तथा सुशासन की प्रभावी स्थापना की दिशा में समन्वित रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से विकसित राजस्थान@ 2047 का एक संतुलित, समावेशी एवं दीर्घकालिक विकास मॉडल साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व एवं सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के समग्र विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में हाल ही में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जयपुर मेट्रो फेज-2 को स्वीकृति और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा की संशोधित लागत को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों निर्णयों से राज्य की प्रगति की गति और अधिक तीव्र, संतुलित एवं दूरगामी होती हुई सुस्पष्ट दिखाई दे रही है।

इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने एक नवोन्मेषी एवं परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है। शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए 'सत्रारंभ के साथ शिक्षारंभ' की अवधारणा से शिक्षा की शुरुआत केवल औपचारिकता तक सीमित न रहकर, आरंभ से ही गुणवत्ता, अनुशासन और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हो रही है।

सुशासन का वास्तविक आकलन इस आधार पर किया जाता है कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान कितनी संवेदनशीलता, तत्परता और प्रभावशीलता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है तथा शासन के सर्वोच्च स्तर पर स्थित नेतृत्व समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति तक किस प्रकार सहज, संवेदनशील एवं प्रभावी संवाद स्थापित कर पाता है। 'राजस्थान संपर्क पोर्टल' और हेल्पलाइन 181 के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं इसकी नियमित समीक्षा और आमजन से सीधे संवाद यह दर्शाता है कि प्रशासन अब अधिक संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है।

प्रदेश सरकार के इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से न केवल प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, बल्कि शासन और आमजन के बीच विश्वास और सहभागिता का संबंध भी प्रगाढ़ हो रहा है। इन्हीं प्रयासों, उपलब्धियों और नवाचारों को समेटे अप्रैल माह का यह अंक आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

वन्दे मातरम्।

(राकेश शर्मा)
प्रधान सम्पादक

आपणो
अग्रणी राजस्थान

राजस्थान दिवस

के पावन अवसर पर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

द्वारा प्रेषित भावसमृद्ध शुभकामना संदेश एवं प्रेरणाप्रद आशीर्वचन

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

श्री भजन लाल शर्मा जी,

राजस्थान दिवस के अवसर पर आपको और राजस्थान की गौरवशाली जनता को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

आपकी सरकार द्वारा राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ मनाने का निर्णय एक अत्यंत सार्थक और दूरदर्शी पहल है। सरदार पटेल भी इस बात के पक्षधर थे कि हमारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक पर्व अपनी परंपराओं और अपनी सांस्कृतिक तिथियों के अनुरूप प्रतिष्ठित हों। ऐसे में यह पहल उस राष्ट्रीय दृष्टि का सम्मान भी है, जो भारत को आत्मबोध से संपन्न और अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सजग देखना चाहती थी।

राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से जितना विशाल है, वहां के लोगों का हृदय भी उतना ही विशाल है। राजस्थान के लोगों ने अपने जीवन और आचरण से यह सिद्ध किया है कि गर्व और आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह वह भूमि है, जहां पीढ़ियों ने पराधीनता का नहीं, बल्कि पूरे स्वाभिमान के साथ बलिदान का पथ चुना।

राजस्थान की यह वीरता केवल इतिहास की गाथा नहीं है, यह आज भी उतनी ही सजीव और सक्रिय है। राज्य के लोग बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों में सेवा देकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। यही साहस और समर्पण राजस्थान को वैश्विक इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों से भी जोड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा का युद्ध इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उस समय भारतीय घुड़सवार सेना ने, विशेष रूप से जोधपुर के वीर सैनिकों ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। हाइफा की मुक्ति आज भी हमें उस अदम्य साहस की याद दिलाती है, जिसका प्रदर्शन राजस्थान ने दुनिया के सामने किया है।

राजस्थान के लोगों की दूरदृष्टि और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता भी उतनी ही प्रेरक है। राज्य के अनेक हिस्सों में जलवायु की परिस्थितियां कठिन हैं। इसके बावजूद यहां के लोगों ने न केवल जीवन को आगे बढ़ाया है, बल्कि निरंतर नए समाधान और अवसर भी निर्मित किए हैं।

यह वही भावना है, जिसकी वजह से, राजस्थान के लोग जहां भी गए, उन्होंने अपनी मेहनत, कौशल और उद्यमशीलता से न केवल सफलता अर्जित की, बल्कि दूसरों का विश्वास भी जीता। राजस्थान की इस परंपरा में दानवीर भामाशाह का वो सेवा भाव भी दिखता है, जिसमें व्यापार केवल समृद्धि का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व का भी प्रतीक बनता है।

राजस्थान की समृद्ध जनजातीय विरासत भी इस राज्य की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे अपना मानगढ़ धाम का वह दौरा आज भी याद है, जब मुझे गोविंद गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला था।

पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने, गुड गवर्नेंस की जो यात्रा तय की है, वह सराहनीय है। राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास को नई गति दी है।

आज राजस्थान में हाईवे, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी कॉरिडोर में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है। कोटपुतली-आगरा ग्रीनफील्ड हाईवे, जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर-अमृतसर कॉरिडोर और जयपुर रिंग रोड के विस्तार जैसे प्रोजेक्ट राज्य में गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स को नई दिशा दे रहे हैं। कुछ सप्ताह पूर्व ही मुझे कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के शिलान्यास का अवसर मिला था। यह एयरपोर्ट आने वाले समय में कोटा और आसपास के क्षेत्रों को नई कनेक्टिविटी, नए निवेश और नए विकास अवसरों से जोड़ेगा। राजस्थान, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण लाभार्थी राज्य है। ये प्रयास राज्य की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाएंगे, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करेंगे और बाजारों के बीच बेहतर जुड़ाव स्थापित करेंगे।

पानी और सिंचाई के क्षेत्र में हो रहा निवेश राजस्थान के विकास में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट अपने व्यापक स्वरूप के साथ राज्य की जल संकट की पुरानी चुनौती को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से भी राज्य को बहुत लाभ होगा। राजस्थान में जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत हजारों आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण भी एक सराहनीय पहल रही है।

मुझे खुशी है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान एक नई पहचान बना रहा है। बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी में बड़े स्तर पर सोलर प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी जोन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का विकास, राज्य को भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहा है।

युवा सशक्तीकरण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी राजस्थान ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विभिन्न परीक्षाओं का सफल आयोजन और 1.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का प्रावधान, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक समय था जब पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं में निराशा और असंतोष व्याप्त था। उस समय सत्ता में बैठे लोगों का रवैया भी संवेदनशील नहीं रहा। अब यह स्थिति बदल रही है और व्यवस्था में भरोसा फिर से स्थापित हो रहा है।

राजस्थान के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार के रूप में हम राज्य की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव सहयोग देते रहेंगे। हमारी प्राथमिकताओं में किसान का कल्याण, युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर, राज्य में उद्योगों का विस्तार और महिलाओं का सशक्तीकरण शामिल रहेंगे। इसके साथ ही, पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाने पर भी हमारा विशेष जोर रहेगा, ताकि दुनिया भर के अधिक से अधिक लोग राजस्थान की समृद्ध विरासत और विशिष्टताओं से परिचित हो सकें।

मुझे विश्वास है कि राज्य के लोगों की सामर्थ्य और कौशल के बल पर राजस्थान अपनी विरासत को आगे बढ़ाता रहेगा। हम मिलकर विकसित राजस्थान–विकसित भारत का सपना जरूर पूरा करेंगे।

एक बार फिर मेरी शुभकामनाएं।

आपका,

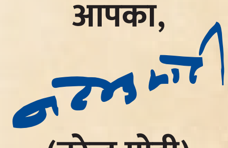

(नरेन्द्र मोदी)

विकास, विश्वास और संवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्राएं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाल की राजस्थान यात्राएं राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 22 मई, 2025 को बीकानेर में उन्होंने 26 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 अमृत भारत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।

25 सितम्बर, 2025 को प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी, साथ ही राजस्थान को 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात दी।

28 फरवरी, 2026 को अजमेर से श्री मोदी ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। प्रदेश को 16 हजार 686 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं दीं और 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

खनिज तेल का वटवृक्ष

रिफाइनरी

गुलाब बत्रा, स्वतंत्र लेखक

मेरे देश की धरती सोना उगले
उगले हीरे मोती- मेरे देश की धरती ...

इस लोकप्रिय फिल्मी गीत को थार मरूस्थल की धरा में समाये खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भण्डार के समुचित दोहन और पचपदरा में तेल रिफाइनरी की स्थापना ने सही मायने में चरितार्थ कर दिया है। धरती के गर्भ में निहित खनिज तेल को काला सोना कहा जाता है। इस अंचल में भीषण गर्मी में लपलपाती लू के थपेड़ों से प्रभावित सुनसान जनजीवन अब अतीत बनता जा रहा है। कभी स्कूली पुस्तकों में दर्ज ऊंघता हुआ शहर जैसलमेर अब देशी-विदेशी पावणों की टोलियों तथा सौर पवन ऊर्जा सहित गैस विद्युत परियोजना से लकदक हो रहा है। वहीं बाड़मेर–सांचौर बेसिन से निकली खनिज तेल की धारा तथा 1926 में सेठ गुलाबचंद सालेचा की अगुवाई में नमक आंदोलन की पीठिका बनी पचपदरा में तेल रिफाइनरी की स्थापना के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल्स हब बनाने की परियोजना ने 'सोने पे सुहागा' कहावत को साकार किया है। इस उपलब्धि से राजस्थान की अर्थव्यवस्था की तकदीर में स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा है।

"यह रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाली 'भाग्यरेखा' सिद्ध होगी।"

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

पचपदरा रिफाइनरी – राजस्थान की आर्थिक प्रगति का आधार

पश्चिमी भारत के सीमा प्रहरी के रूप में राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत है। लेकिन, थार मरूस्थल के गर्भ में उपलब्ध खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भण्डार के लिए पिछले दशकों से सर्वे, अन्वेषण तथा दोहन से ना केवल राजस्थान, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान का गौरवपूर्ण अवसर मिला है। बाड़मेर जिले से पृथक हुए बालोतरा जिले के पचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना की गई है। इस रिफाइनरी की एक विशेषता यह है कि प्रसंस्करण के दौरान किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं होगा। इसके लिए जीरो लिक्विड इफ्लूएंट डिस्चार्ज की व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रिक हीटेड पाइप लाइन

बाड़मेर जिले में वेदान्ता समूह के मंगला ऑयल फील्ड से पचपदरा रिफाइनरी तक क्रूड ऑयल पहुंचाने के लिए लगभग 74 किमी लम्बाई में इलेक्ट्रिक हीटेड पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। मंगला ऑयल फील्ड क्षेत्र में रोजाना लगभग 80 हजार बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है। रिफाइनरी की मांग बढ़ने पर उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए नये तेल कुओं की खुदाई एवं सर्वेक्षण प्रकिया जारी है। कंपनी लगभग तीन हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल उत्पादन कर रही है। पचपदरा रिफाइनरी में उत्पादन के लिए क्रूड ऑयल की आपूर्ति अरब देशों से की गई है।

राजस्थान रिफाइनरी – रोजगार, निवेश और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आधार

पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी भारत की प्रमुख इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना है, जिसे एच.पी.सी.एल. (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड) और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम एच.आर.आर.एल. द्वारा विकसित किया गया है। यह परियोजना 4 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित है तथा इसकी वार्षिक क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसमें पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। इस रिफाइनरी से केन्द्र और राज्य सरकार को राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ-साथ हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल हब के माध्यम से अनेक बायो-प्रोडक्ट से विभिन्न उद्योगों का विकास होगा, जिससे राज्य के औद्योगिक ढांचे को नया आयाम मिलेगा। यह परियोजना बड़े निवेश का उदाहरण होने के साथ-साथ भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पेट्रोलियम क्षेत्र में संस्थानों और कंपनियों की भूमिका

पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस सहित एल. एन. जी. का हमारे जन जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर जनमानस की प्रतिक्रिया शासन-प्रशासन के लिए मायने रखती है। स्वाधीनता के पश्चात् तेल एवं गैस की खोज के लिए प्रयास आरम्भ हुए। वर्ष 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) की स्थापना की गई। इसी क्रम में ऑयल इण्डिया लि. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. तथा गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। केन्द्र सरकार के साथ पब्लिक सेक्टर को इस कार्य में जोड़ा गया। समय चक्र में नीतियां बनीं। विदेशी कम्पनियां भी इस दौड़ में शामिल हुईं। रिलायंस, एस्सार नायरा तथा केयर्न इण्डिया (वेदांता समूह) इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हैं।

रागेश्वरी का ज्वालामुखी

रामायण के एक प्रसंग के अनुसार लंका पर चढ़ाई के दौरान अनुनय-विनय के बावजूद समुद्र में मार्ग नहीं मिलने पर भगवान श्रीराम ने धनुष बाण संधान लिया। अन्तत: समुद्र में मार्ग मिलने पर श्रीराम ने वह तीर जिस दिशा में छोड़ा, वहां समुद्र लहलहाता था, जो कालचक्र में थार मरूस्थल में परिवर्तित हुआ। भू-विज्ञानियों के गहन अध्ययन एवं शोध से इस प्रसंग की पुष्टि रोचक जानकारी से होती है। भू-वैज्ञानिकों की अवधारणा के अनुसार क्रिटेशियस काल के आरम्भ एवं अंतिम खण्ड में तीव्र भू-वैज्ञानिकी हलचलों तथा पृथ्वी पर उच्च तापक्रम और दाब का अत्यंत असाधारण घटनाक्रम हुआ। ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड टकराने अथवा ज्वालामुखी फटने से घटित इस घटना से समुद्र विलुप्त होने के साथ-साथ विशालकाय डायनासोर, शार्क थल जलचर जीव जंतुओं की प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। समय-चक्र में जल-थल की ये प्रजातियां पृथ्वी में दबे रहने और ताप एवं दाब की प्रक्रिया में परिवर्तित होती गईं। समुद्र तल में इनके जमाव तथा समुद्री पदार्थो के रासायनिक संगठन की प्रक्रिया में तेल एवं गैस के लिए सहज रूप से कच्चा माल उपलब्ध होता गया। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हाइड्रोकार्बन के निर्माण से अथाह तेल भंडार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

बाड़मेर क्षेत्र में पेट्रोलियम खोज और भूगर्भीय संरचना

विश्व में तेल उत्पादन में अग्रणी देश सऊदी अरब, सेनेगल व मोरक्को में मिले जीवाश्म बाड़मेर में खोजे गए विभिन्न जीवाश्मों से मिलते-जुलते है। बाड़मेर में 1700 मीटर गहराई पर तेल मिला है। वर्तमान बाड़मेर जिले के सारनू एवं मूंदवाड़ा में अवस्थित ज्वालामुखी फटने से सागर सूख गया तथा इंडियन टेक्टोनिक प्लेट से मेडगास्कर अलग हो गया। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में इसी ज्वालामुखी इलाके की पहचान रागेश्वरी नाम से की गई। केयर्न इण्डिया ने यहां तेल गैस कुओं की खुदाई, की जिसे आर.जे. टी. (रागेश्वरी गैस टर्मिनल) कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी, बेन्टोनाइट के भंडार वाले इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस अधिक मात्रा में मिली है, जिससे बिजली बन रही है।

हाथियों से शुरू हुई तेल खोज की कहानी

तेल गैस एवं अकूत खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध राजस्थान की पिछले दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में पहचान

बनी है। भारत में तेल खोज की कहानी दो सौ साल पहले शुरू हुई और तेल खोज में हाथी सहायक बने। दरअसल, असम के जंगलों में रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। वर्ष 1889 में डिगबोई (असम) के जंगलों में हाथी पर सवार असम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के मुख्य ब्रिटिश इंजीनियर बिली लिओवा लेक को हाथियों के पैरों पर तेल के निशान दिखाई दिए। बस बिली ने कम्पनी से समझाइश कर तेल कूप की खुदाई करवाई। मजदूरों को ड्रिलिंग के दौरान डिग–बॉय–डिग (खोदो–बालक–खोदो) संबोधन के चलते वह स्थल डिगबोई के नाम से प्रचलित हो गया और 12 साल बाद वर्ष 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी की स्थापना से भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत हुई।

जीवाश्म से पेट्रोलियम तक का सफर

पुरातन काल में सागर की विशाल तरंगों की क्रीड़ा स्थली के प्राकृतिक रूप में हिमालय से प्राचीन अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित पश्चिमी राजस्थान कालचक्र की चपेट में बालुका राशि से आच्छादित हो गया। विशाल सागर के अवशेष कच्छ के रण के रूप में दृष्टिगोचर हैं, तो बालुका राशि के नीचे पेट्रोलियम सम्पदा भू–सरंचना का रहस्य बन गई, जिसकी परतें खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के रूप में खुलती जा रही है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र से खनिज तेल की खोज आरम्भ हुई। बाड़मेर–सांचौर बेसिन में वर्ष 2004 में खनिज तेल के लिए खुदाई को मंगला नाम मिला, जिसे तब विश्व की सबसे बड़ी खोज माना गया।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र बाड़मेर–सांचौर बेसिन, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार के कारण देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंगला तेल क्षेत्र से लेकर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तक की यात्रा ने न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है, बल्कि रोजगार सृजन, राजस्व वृद्धि और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को भी सशक्त किया है। तेल एवं गैस की खोज से जुड़े ऐतिहासिक, भूगर्भीय और संस्थागत प्रयास यह दर्शाते हैं कि भारत का पेट्रोलियम क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस प्रकार यह समूचा परिदृश्य राजस्थान को “ऊर्जा और खनिज संपदा का उभरता केंद्र” बनाते हुए भारत की आर्थिक प्रगति में इसकी निर्णायक भूमिका को स्थापित करता है। ■

विकसित राजस्थान@2047 के सशक्त आधार

देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगी

राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा

79,459 करोड़ रुपये

विकास का ग्रोथ इंजन साबित होगा

मेट्रो फेज-2

13,038 करोड़ रुपये

> **"ये रिफाइनरी राजस्थान की तकदीर भी बदलेगी, यहां की तस्वीर भी बदलेगी। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो ऊर्जा यहीं से चल पड़े और देश के हर कोने में पहुंचे।"**
>
> **– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी**

(बाड़मेर में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्य की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह में)

वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव

किसी भी राज्य का वास्तविक विकास केवल भौतिक संरचनाओं के विस्तार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी दूरदर्शी और समन्वित नीति-प्रणाली पर आधारित होता है, जो वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं के मध्य संतुलन स्थापित कर सके। सतत, समावेशी और संरचित विकास की यही अवधारणा सुशासन की पहचान बनती है। इसी व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य में एक ओर पचपदरा रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उपक्रम आर्थिक सुदृढ़ता और निवेश को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहरी परिवहन को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए मेट्रो परियोजनाएं गति पकड़ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के समग्र विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंजूरी दी गई, वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा की संशोधित लागत को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं के महत्व को समग्र परिप्रेक्ष्य में आंकने हेतु भारत एवं राजस्थान में मेट्रो रेल तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षेत्र के विकास क्रम का संक्षिप्त अवलोकन प्रासंगिक है।

कच्चे तेल से उपयोगी ईंधन तक – रिफाइनरी की भूमिका

रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाना), एक ऐसा औद्योगिक संयंत्र है, जहां कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) को परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट ईंधन और एलपीजी जैसे उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। यह जमीन से निकले कच्चे तेल को सीधे उपयोग योग्य ईंधनों में बदलने का काम करती है, जो ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक है। आधुनिक रिफाइनरी तंत्र के विकास से पूर्व कच्चे तेल का उपयोग अत्यंत सीमित एवं असंगठित रूप में होता था, जिसमें प्राकृतिक तेल स्रावों का उपयोग मुख्यतः स्थानीय एवं पारंपरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित था। औद्योगिक क्रांति के साथ ऊर्जा की बढ़ती मांग ने कच्चे तेल के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी में डिस्टिलेशन आधारित रिफाइनिंग तकनीकों का विकास हुआ।

एशिया के प्रमुख रिफाइनिंग हब के रूप में उभरता भारत

भारत में डिगबोई में 1901 में स्थापित रिफाइनरी ने देश में पेट्रोलियम उद्योग के संगठित विकास की आधारशिला रखी। भारत का पेट्रोलियम उद्योग समय के साथ तकनीकी प्रगति और नीतिगत सुधारों के कारण निरंतर सुदृढ़ हुआ है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद इस क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, जिससे अन्वेषण और परिशोधन गतिविधियों में विस्तार हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात में स्थित जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसने भारत की परिशोधन क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। इसके परिणामस्वरूप भारत एशिया के प्रमुख रिफाइनिंग हब के रूप में उभरा है।

पचपदरा रिफाइनरी परियोजना – क्षमता एवं संरचना

बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी–सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है। पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एचआरआरएल द्वारा किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इस संयुक्त उपक्रम में एचपीसीएल की 74 प्रतिशत तथा राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

वित्तीय स्वीकृति एवं विस्तार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरएल) परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत 43,129

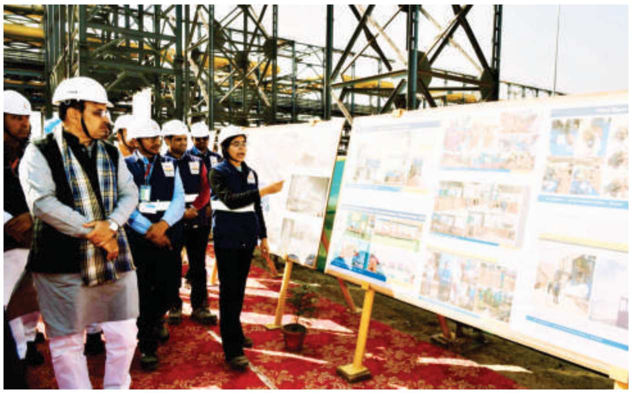

करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस वृद्धि के बाद एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा एक वृहद रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कुल उत्पादन का 26 प्रतिशत से अधिक भाग पेट्रोकेमिकल उत्पादों का होगा। यह रिफाइनरी प्रति वर्ष लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल के साथ-साथ पॉलीप्रोपाइलीन, एलएलडीपीई, एचडीपीई तथा बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडीन जैसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी उत्पादन करेगी। ये उत्पाद परिवहन, फार्मा, पेंट और पैकेजिंग जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यह परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक होगी।

> **“पचपदरा रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा और साथ ही, इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति भी मिलेगी। यह परियोजना ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की आयात पर निर्भरता को कम करेगी। साथ ही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध होंगे।”**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

ऊर्जा सुरक्षा एवं औद्योगिक विकास में योगदान

यह परियोजना देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, पेट्रोकेमिकल उत्पादों की मांग तथा विशेष औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी एवं विदेशी मुद्रा की बचत संभव होगी। साथ ही यह पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को गति प्रदान करेगी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे तेल के उपयोग के साथ यह परियोजना भारत को एक प्रमुख रिफाइनिंग हब के रूप में स्थापित करने में भी योगदान देगी।

रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तीकरण

परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान लगभग 25,000 श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं जबकि इसके संचालन के पश्चात 5,000 से अधिक स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर एवं जोधपुर क्षेत्रों में पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के राजस्व विशेषत: वैट एवं जीएसटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रभावी परिवहन समाधान

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और यातायात के बढ़ते दबाव के बीच मेट्रो रेल प्रणाली एक प्रभावी, समयबद्ध एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन समाधान के रूप में उभरी है। यह न केवल आवागमन को सुगम बनाती है, बल्कि शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए ऊर्जा दक्षता एवं सतत विकास के लक्ष्यों को भी सुदृढ़ करती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मेट्रो रेल का विकास

मेट्रो रेल प्रणाली का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ, जब लंदन अंडरग्राउंड के रूप में विश्व की पहली मेट्रो सेवा वर्ष 1863 में प्रारंभ की गई। समय के साथ यह प्रणाली भाप आधारित संचालन से विकसित होकर विद्युत संचालित एवं अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हो गई। इसके पश्चात विश्व के प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का तीव्र विस्तार हुआ और आज टोक्यो, न्यूयॉर्क तथा पेरिस जैसे महानगरों की मेट्रो प्रणालियां शहरी परिवहन के सशक्त एवं विश्वस्तरीय मॉडल के रूप में स्थापित हैं।

भारत में मेट्रो रेल का विकास

भारत में मेट्रो रेल का औपचारिक विकास वर्ष 1984 में कोलकाता मेट्रो के संचालन से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। इसकी सफलता के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार हुआ और आज जयपुर सहित अनेक शहरों में यह प्रणाली शहरी गतिशीलता का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है।

भारत के मेट्रो मैन ई. श्रीधरन

ई. श्रीधरन भारत के 'मेट्रो मैन' के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसी परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया। उनके कार्यों ने भारत में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप दिया। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में विकसित परियोजनाओं ने समयबद्धता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के उच्च मानक स्थापित किए, जो आज भी देश की मेट्रो परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं।

राजस्थान में मेट्रो का विकास

राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत राजधानी जयपुर से हुई। तीव्र शहरीकरण और बढ़ते यातायात दबाव के कारण एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के आधार पर जयपुर मेट्रो परियोजना को प्रारंभ किया गया, जिसने शहरी गतिशीलता को नई दिशा प्रदान की। जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण वर्तमान में सफलतापूर्वक संचालित है। इसमें प्रतिदिन लगभग 60 हजार यात्री यात्रा करते हैं। पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 11.64 किलोमीटर लंबा मार्ग विकसित किया गया है, जिसमें 11 स्टेशन शामिल हैं। ये स्टेशन शहर के प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को परकोटे से जोड़ते हैं।

"मेट्रो आधुनिक भारत के शहरों के लिए एक नई जीवनरेखा बन रही है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

"जयपुर मेट्रो फेज-2 जयपुर शहर के समग्र विकास का ग्रोथ इंजन सिद्ध होगा। इससे शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा एवं वीकेआई को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।"

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

जयपुर मेट्रो – द्वितीय चरण (फेज-2)

जयपुर मेट्रो का प्रस्तावित द्वितीय चरण शहर के प्रमुख आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। यह वर्तमान कॉरिडोर का पूरक होगा और समूचे जयपुर में व्यापक मेट्रो संपर्क सुनिश्चित करेगा। इस चरण के अंतर्गत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआई), जयपुर हवाई अड्डा, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल एवं स्टेडियम, अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर जैसे प्रमुख केंद्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में हवाई अड्डा क्षेत्र में एक भूमिगत स्टेशन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, नियोजित इंटरचेंज एवं फीडर सेवाओं के माध्यम से इसे वर्तमान में संचालित प्रथम चरण से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे शहर में एक एकीकृत, सतत एवं सुगम मेट्रो नेटवर्क की स्थापना सुनिश्चित होगी।

केंद्रीय स्वीकृति एवं परियोजना विवरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस चरण के अंतर्गत लगभग 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत से 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक विस्तारित इस मार्ग में कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह परियोजना भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की 50:50 हिस्सेदारी वाले संयुक्त उपक्रम राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा एवं जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी परियोजनाएं राजस्थान के विकास को केवल गति ही नहीं दे रही हैं, बल्कि उसे एक ठोस, संतुलित और दीर्घकालिक आधार भी प्रदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य के समन्वित प्रयास राजस्थान को औद्योगिक निवेश, ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं सतत निगरानी से सुशासन की भावना सुदृढ़ हुई है। इन समन्वित पहल से 'विकसित राजस्थान @2047' के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित हो रही है।■

हरित विकास का आधार स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार

डॉ. गोरधन लाल शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति और जीवन के मध्य गहरे पारस्परिक संबंध को अत्यंत सूक्ष्मता से समझाया गया है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि समस्त सृष्टि एक संतुलित प्राकृतिक चक्र पर आधारित है, जिसमें अन्न, वर्षा और जीवन एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जब यह चक्र संतुलित रहता है, तभी मानव जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का समग्र विकास संभव होता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहां ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी चुनौतियां तेजी से उभर रही हैं, वहां इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना एक बड़ी आवश्यकता बन गया है। ऐसे समय में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के समन्वय से विकसित समाधान ही सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। साथ ही पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न वर्तमान वैश्विक हालात के चलते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में पूरे विश्व के लोगों की रुचि बढ़ रही है। इसी संदर्भ में, ग्रामीण भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग विशेषकर गोबर गैस (बायोगैस) के माध्यम से एक प्रभावी, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है, जो न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है, बल्कि "कचरे से कंचन" की अवधारणा को साकार करते हुए आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करता है।

कचरे से कंचन तक

गोबर गैस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना

सस्ती एवं सुलभ तकनीक के रूप में गोबर गैस

गोबर गैस उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक सरल, किफ़ायती तथा आसानी से अपनाई जा सकने वाली है, जिसे स्थापित करना भी अपेक्षाकृत सहज होता है। विशेषकर छोटे स्तर पर इसके लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैविक अवशेष, रसोई के कचरे तथा पशुधन के गोबर का उपयोग कर घरेलू स्तर पर छोटे बायोडाइजेस्टर संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जो समय के साथ अपनी लागत की भरपाई कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चा माल प्राय: नि:शुल्क एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध होता है, जिससे इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और अधिक सुदृढ़ हो जाती है। उत्पादित बायोगैस का उपयोग सीधे भोजन पकाने एवं विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, जो इसे एक अत्यंत उपयोगी और किफ़ायती ऊर्जा विकल्प बनाता है। उदाहरण के लिए एक पशुधन से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ से इतनी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है कि उससे पूरे दिन एक बल्ब को प्रज्वलित रखा जा सके, जो इसकी दक्षता और उपयोगिता को स्पष्ट करता है।

क्या है गोबर गैस?

गोबर गैस, जिसे वैज्ञानिक रूप से बायोगैस कहा जाता है, एक प्रकार की जैविक गैस है, जो पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट तथा अन्य जैविक कचरे के ऑक्सीजन रहित अपघटन (एनारोबिक डायजेशन) की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। यह एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण-अनुकूल ज्वलनशील गैसीय ईंधन है, जिसमें मुख्यत: मीथेन (लगभग 55–60 प्रतिशत) तथा कार्बन डाइऑक्साइड (लगभग 35–40 प्रतिशत) पाई जाती है, जबकि अल्प मात्रा में अन्य गैसें एवं वाष्प भी उपस्थित रहती हैं। अपनी संरचना और गुणों के कारण यह एक प्रभावी ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोगी है। उत्पादित बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने, विद्युत उत्पादन तथा शुद्धिकरण के पश्चात वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय और टिकाऊ विकल्प के रूप में स्थापित होती है।

गोबर गैस उत्पादन के लिए कच्चा माल

गोबर गैस उत्पादन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया पर आधारित है तथा इसके संचालन के लिए किसी अतिरिक्त ईंधन या बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इसमें प्रयुक्त कच्चा माल निरंतर उपलब्ध एवं नवीकरणीय होता है, क्योंकि पेड़-पौधे और फसलें सतत रूप से विकसित होती रहती हैं। गोबर, खाद्य अपशिष्ट तथा फसल अवशेष जैसे संसाधन ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे यह एक अत्यंत टिकाऊ एवं व्यावहारिक विकल्प सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार का जैविक अपशिष्ट या सजीव बायोमास जैसे पशुओं का गोबर, पेड़-पत्तियां, फसलों के तने, मानव अपशिष्ट, जलकुंभी तथा तेल निष्कासन के बाद बची खली का उपयोग बायोगैस उत्पादन में किया जा सकता है, जो इसकी व्यापक उपयोगिता और संसाधन विविधता को दर्शाता है।

Bio Waste के पर्यावरण अनुकूल उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु नगर निगम जयपुर एवं जोधपुर में PPP Mode पर Compressed Bio Gas (CBG) Plants की स्थापना की जाएगी।

टिकाऊ विकास में गोबर गैस की भूमिका

गोबर गैस टिकाऊ विकास के सिद्धांतों को साकार करने वाला एक प्रभावी माध्यम है, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा समाज तीनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी और कोयले पर निर्भरता को कम करती है, जिससे वनों की कटाई में कमी आती है तथा प्रदूषण नियंत्रित होता है। साथ ही, बायोगैस एक स्वच्छ ईंधन होने के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने में सहायक होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि गोबर एवं अन्य जैविक कचरे का वैज्ञानिक एवं उपयोगी निपटान संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त, गैस उत्पादन के पश्चात प्राप्त स्लरी उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद में परिवर्तित हो जाती है, जो मृदा उर्वरता को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करती है। इस प्रकार, गोबर गैस एक समग्र एवं सतत समाधान के रूप में उभरती है।

एलपीजी और सीएनजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में गोबर गैस

भारत प्रतिवर्ष एलपीजी और सीएनजी के आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करता है, जिससे आर्थिक दबाव उत्पन्न होता है। इस परिप्रेक्ष्य में गोबर गैस एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरती है, जो इस निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से घरेलू रसोई गैस की आवश्यकता स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सकती है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता घट सकती है। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर बायोगैस का शुद्धीकरण कर उसे बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग वाहनों एवं अन्य ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जा सकता है। इस प्रकार, गोबर गैस ऊर्जा के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे गांव स्वयं अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बनते हैं और "ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत" की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार होता है।

मरुस्थलीय क्षेत्रों में बायोगैस की संभावनाएं

राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को लेकर यह धारणा प्रचलित है कि पानी की कमी के कारण इनका संचालन संभव नहीं है। किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की डिज़ाइन विकसित की गई है, जिनमें ताजे गोबर का उपयोग बिना पानी मिलाए भी किया जा सकता है और प्रभावी रूप से गैस का उत्पादन संभव होता है। यद्यपि ऐसे संयंत्रों के संचालन हेतु कुछ विशेष सावधानियों एवं तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है, फिर भी ये जल-अभाव वाले क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन का एक व्यावहारिक और उपयोगी समाधान प्रस्तुत करते हैं।

बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया

बायोगैस उत्पादन एक जैव-रासायनिक प्रक्रिया है, जो मुख्यत: दो चरणों में संपन्न होती है, जिन्हें क्रमश: अम्ल निर्माण स्तर तथा मीथेन निर्माण स्तर कहा जाता है। प्रथम चरण में गोबर एवं अन्य जैविक अपशिष्ट में उपस्थित अम्ल-निर्माण करने वाले जीवाणु जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपघटित कर सरल कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित करते हैं। चूंकि इस स्तर पर मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्गेनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं, अत: इसे अम्ल निर्माण चरण कहा जाता है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु (मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया) इन कार्बनिक अम्लों पर क्रियाशील होकर उन्हें

मीथेन गैस में परिवर्तित करते हैं, जो बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। इस प्रकार यह द्विस्तरीय प्रक्रिया जैविक अपशिष्ट को उपयोगी ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करती है।

बायोगैस संयंत्र के लिए भूमि की आवश्यकता

सामान्यत: एक छोटे बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग 25 फीट लंबाई एवं 15 फीट चौड़ाई वाली खुली भूमि की आवश्यकता होती है। संयंत्र स्थापित हो जाने के पश्चात यह भूमि प्राय: समतल दिखाई देती है, जिसका उपयोग सामान्य आवागमन के लिए भी किया जा सकता है। संयंत्र से निकलने वाली स्लरी के प्रबंधन हेतु खाद के गड्ढे बनाए जा सकते हैं, जहां इसे सुखाकर एकत्रित किया जाता है अथवा पाइप या नालियों के माध्यम से सीधे खेतों तक पहुंचाकर उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार सीमित भूमि में भी बायोगैस संयंत्र का प्रभावी संचालन संभव है।

गोबरधन योजना – एक पहल और संभावनाएं

ग्रामीण भारत में बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARdhan) योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना के माध्यम से गोबर एवं अन्य जैविक कचरे का उपयोग कर ऊर्जा तथा जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्वच्छता, ऊर्जा और कृषि तीनों क्षेत्रों को लाभ मिलता है। भारत में लगभग 30 करोड़ से अधिक पशुधन उपलब्ध है, जिससे प्रतिदिन विशाल मात्रा में गोबर उत्पन्न होता है। यदि इस संसाधन का वैज्ञानिक एवं सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति करने में सक्षम हो सकता है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बना सकता है।

राजस्थान हरित ऊर्जा की दिशा में ठोस कदम

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने हरित ऊर्जा और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस क्रम में वर्ष 2026–27 के हरित बजट में बजट में बायो-वेस्ट के पर्यावरण-अनुकूल उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर एवं जोधपुर नगर निगम क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई हैं। ये पहल राज्य में बायोगैस एवं बायो-सीएनजी के विस्तार को गति प्रदान करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक सशक्त आधार प्रस्तुत करती है।

चुनौतियां एवं समाधान

यद्यपि गोबर गैस के क्षेत्र में संभावनाएं अत्यंत व्यापक हैं, तथापि इसके प्रसार में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी विद्यमान हैं। प्रमुख रूप से प्रारंभिक लागत तथा तकनीकी जानकारी का अभाव इसके व्यापक क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के साथ-साथ संयंत्रों के रखरखाव एवं संचालन से संबंधित कठिनाइयां भी सामने आती हैं। हालांकि, इन चुनौतियों का समाधान संभव है। सरकारी सहायता एवं सब्सिडी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत वित्तीय सहयोग, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इन बाधाओं को प्रभावी रूप से दूर किया जा सकता है, जिससे बायोगैस के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

गोबर गैस केवल एक वैकल्पिक ईंधन नहीं, बल्कि भारत के टिकाऊ विकास का एक समग्र आधार है, जो ऊर्जा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों को सुदृढ़ करता है। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे युद्धों और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयातित ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी राष्ट्र के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। ऐसे समय में गोबर गैस जैसे स्वदेशी एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बना सकते हैं। यदि इसे व्यापक स्तर पर अपनाया जाए, तो न केवल एलपीजी और सीएनजी पर निर्भरता कम की जा सकती है, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार “कचरे से कंचन” की अवधारणा वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक बन गई है, जो देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सुरक्षित, हरित भविष्य की ओर अग्रसर करती है। ■

खाकी का मानवीय चेहरा

कर्तव्य और करुणा की प्रेरक गाथाएं

डॉ. कमलेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक

मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित राजस्थान पुलिस की 10 वीर नारियां, जिन्होंने साहस और संवेदनशीलता से सुरक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किए

राजस्थान पुलिस की खाकी वर्दी सिर्फ कानून-व्यवस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और साहस का भी जीवंत उदाहरण है। हाल ही में सामने आई प्रेरक कहानियों में जहां एक ओर महिला पुलिसकर्मियों ने अपने साहस, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा से यह साबित कर दिया कि वर्दी में मातृत्व और मजबूती दोनों साथ चल सकते हैं। वहीं पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी कठिन परिस्थितियों में देवदूत बनकर लोगों की जिंदगी बचाई और ईमानदारी की मिसाल पेश की।

मुख्यमंत्री आवास पर गूंजा राजस्थान पुलिस की नारी शक्ति का विजयघोष

कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की बाजी लगाने वाली और खेल के मैदान में तिरंगा लहराने वाली राजस्थान पुलिस की 10 जांबाज महिला पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस को उस समय सर्वोच्च पहचान मिली, जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित कर उनसे सीधा संवाद किया। बैंक लूट की फायरिंग के बीच अपराधियों को दबोचने वाली निडरता, उग्र भीड़ के चक्रव्यूह से एक विक्षिप्त महिला की जान बचाने वाली सूझबूझ और उफनती नहर के काल रूपी पानी में छलांग लगाकर डूबती महिला को सुरक्षित बाहर निकालने वाले अदम्य साहसिक कार्यों को मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सराहा।

खाकी में नारी शक्ति

साहस, संवेदनशीलता और संकल्प की कहानियां

अजेय साहस और न्याय का संकल्प : अलवर पुलिस की जांबाज महिला अधिकारी डॉ. पूनम

अलवर की महिला अपराध अनुसंधान इकाई में डीवाईएसपी डॉ. पूनम ने अपनी त्वरित जांच क्षमता और प्रभावी कार्यशैली से अरावली विहार और एनईबी क्षेत्रों में मासूम बच्चियों के साथ हुए जघन्य अपराधों के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय की उम्मीद दिलाई। उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को प्रताड़ित करने वाले रिटायर्ड अधिकारी और शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले प्रभावशाली अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। वर्ष 2024 के विशेष अभियान में 13 इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी कर उन्होंने साबित किया कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता

कानून व्यवस्था और त्वरित न्याय की मिसाल एसएचओ गुंजन वर्मा

जयपुर आयुक्तालय के नारायण विहार थाने की प्रभारी गुंजन वर्मा ने एक विदेशी महिला से जुड़े गंभीर दुष्कर्म मामले में सिर्फ 48 घंटे के भीतर चार्जशीट पेश कर तेज और प्रभावी कार्रवाई की मिसाल पेश की। साथ ही, नए आपराधिक कानूनों को सही तरीके से लागू कर उन्होंने आधुनिक और बेहतर पुलिसिंग को भी मजबूत किया है।

अपराध नियंत्रण और जांच में अग्रणी उप निरीक्षक सोनाली शर्मा

घर में घुसकर वृद्ध महिला शायरी बाई की नृशंस हत्या और लूट जैसे सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करना हो या मंदिर की पवित्रता को भंग करने वाले चोरों को दबोचकर माल बरामद करना। राजसमंद जिले की उपनिरीक्षक सोनाली शर्मा (डीएसटी प्रभारी) ने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और तीक्ष्ण अनुसंधान कौशल का परिचय देते हुए अपराध की जटिल से जटिल गुत्थियों को सुलझाकर अपराधियों के रसूख को कानून के पैरों तले कुचल दिया है। बनेडिया गांव में सोने के जेवर लूटने और जानलेवा हमला करने वाले खतरनाक गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाने से लेकर, अपहरण किए गए एक मासूम नवजात बच्चे को सुरक्षित बरामद करने तक, इनका हर कदम मानवीय संवेदनाओं और पेशेवर दक्षता का अनूठा संगम रहा है।

हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने खेलों के मैदान में लहराया परचम

अपनी एकाग्रता और अटूट संकल्प के दम पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में जयपुर पांचवी आरएसी की महिला हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने 09 स्वर्ण, 07 रजत और 01 कांस्य पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी न केवल अपराधियों के लिए काल है, बल्कि खेल के मैदान में भी अजेय है।

डॉ. पूनम
आरपीएस

धोली बाई
कांस्टेबल

सोनाली शर्मा
एसआई

गायत्री देवी
हेड कांस्टेबल

मेनका कुमारी
कांस्टेबल

गंगा डामोर
कांस्टेबल

विमला
हेड कांस्टेबल

रितु राठौड़
कांस्टेबल

गुंजन वर्मा
इंस्पेक्टर

सरोज चौधरी
कांस्टेबल

हेड कांस्टेबल विमला की सूझबूझ ने पकड़ा लाखों की लूट का मामला

सिरोही के आबूरोड सदर थाने की हेड कांस्टेबल विमला विश्नोई ने अपनी सतर्कता और त्वरित निर्णय से 32.48 लाख रुपये की लूट की वारदात को नाकाम कर दिया। संदिग्धों की हरकत भांपकर उन्होंने तुरंत सूचना देकर घेराबंदी करवाई और अपराधियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी दी गई जानकारी के आधार पर 10.69 लाख रुपये की राशि भी बरामद की गई।

खेलों में स्वर्ण और पुलिस का गौरव हेड कांस्टेबल रितु राठौर

द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा की कांस्टेबल रितु राठौर ने प्रथम अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर (2024) में अपनी शक्ति का लोहा मनवाकर स्वर्ण पदक पर जीता। साथ ही, उन्होंने 72वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर (2023-24) में भी अपने उत्कृष्ट खेल कौशल और टीम भावना का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर विजय का परचम लहराया।

महिला गरिमा और सुरक्षा की रक्षक कांस्टेबल सरोज चौधरी

जयपुर आयुक्तालय के अभय कमांड में तैनात कांस्टेबल सरोज चौधरी ने महिला हेल्पलाइन 1090 पर मिली शिकायतों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए 4735 में से 4581 मामलों का सफल निस्तारण किया। उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत 118 निरोधात्मक कदम और 32 आपराधिक मामले दर्ज करवाए, वहीं 4431 मामलों में समझाइश और अन्य माध्यमों से समाधान कर कई परिवारों को टूटने से बचाया।

कांस्टेबल गंगा ने अपनी जान दांव पर लगाकर बचाई महिला की जिंदगी

बांसवाड़ा के कोतवाली थाने की कांस्टेबल गंगा डामोर ने उफनती कागदी नहर में बह रही एक महिला को बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत छलांग लगा दी। तेज बहाव के बीच उन्होंने साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह घटना उनके समर्पण, बहादुरी और मानवता के प्रति सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है।

बैंक लुटेरों से भिड़ गई कांस्टेबल मेनका कुमारी

जयपुर पश्चिम के झोटवाड़ा थाने की कांस्टेबल मेनका कुमारी ने पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट और फायरिंग के दौरान अदम्य साहस दिखाते हुए बिना अपनी जान की परवाह किए अपराधियों का सामना किया। त्वरित निर्णय और बहादुरी से उन्होंने मौके पर ही लुटेरों को पकड़ लिया। यह घटना उनकी कर्तव्यनिष्ठा और साहस का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत किया।

उग्र भीड़ के बीच देवदूत बनीं कांस्टेबल धोली बाई

जयपुर आयुक्तालय के मालपुरा गेट थाने की कांस्टेबल धोली बाई ने 150–200 लोगों की उग्र भीड़ के बीच अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक विक्षिप्त महिला की जान बचाई। उन्होंने बिना अपनी परवाह किए भीड़ का सामना किया, महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया और समझाइश से दोनों समुदायों के बीच तनाव भी शांत कराया।

देवदूत बने राजस्थान पुलिस के जांबाज

मौत के साए में भी नहीं डगमगाए कदम : करंट के बीच पुलिस ने खींच ली जिंदगी

जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में तेज अंधड़ और बारिश के दौरान एक टिनशेड गिरने से एक महिला मलबे में दब गई, चारों ओर करंट से भरे तार फैले थे। ऐसे खतरनाक हालात में हेड कांस्टेबल भागीरथ और चालक हंसराज मौके पर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे तुरंत एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी जान बच गई।

पुलिस की मुस्तैदी ने लौटाई दिल्ली के युवा चेहरे की मुस्कान

दिल्ली से आए एक युवक का बैग सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ऑटो में छूट गया, जिसमें जरूरी सामान और दस्तावेज थे। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल गणेश लाल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑटो की पहचान कर उसे ढूंढ निकाला और बैग सुरक्षित युवक को लौटा दिया। बैग वापस मिलने पर युवक ने भावुक होकर हेड कांस्टेबल गणेश लाल का शुक्रिया अदा किया और जयपुर पुलिस की जमकर तारीफ की।

ईमानदारी की मिसाल : अजमेर पुलिस ने गरीब ऑटो चालक का 30 हजार रुपयों से भरा बैग लौटाया

अजमेर के वैशाली नगर निवासी टैम्पो चालक महेन्द्र भाटी का बैग रास्ते में गिर गया, जिसमें 30,000 रुपये और जरूरी दस्तावेज थे। आदर्श नगर थाने के कांस्टेबल अरविन्द चौधरी को बैग मिला, तो उन्होंने राजकॉप सिटीजन ऐप की मदद से मालिक का पता लगाकर उसे सुरक्षित लौटा दिया। बैग और मेहनत की कमाई वापस पाकर चालक भावुक हो गया और पुलिस का आभार जताया।

महज 1 घंटे में 7 साल के मासूम को मिलाया परिवार से

अजमेर के इंडिया मोटर सर्किल के पास भटके 7 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर महज 1 घंटे में उसके परिवार से मिला दिया। कोतवाली थाने के एएसआई शिवलाल और कांस्टेबल विनोद कुमार ने बच्चे से जानकारी लेकर तुरंत परिजनों से संपर्क किया।

'रियल लाइफ हीरो' बने कांस्टेबल अशोक कुमार

झालावाड़ के कांस्टेबल अशोक कुमार ने 12 वर्षीय बालिका को दरिंदे के चंगुल से सुरक्षित बचाकर अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्ची को रेस्क्यू किया और भागते हुए आरोपी को पीछा कर पकड़ लिया।

देवदूत बनकर आए कांस्टेबल मानसिंह

अजमेर में घरेलू विवाद से परेशान एक बुजुर्ग आनासागर झील में कूद गए। मौके पर मौजूद कांस्टेबल चालक मानसिंह ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बाद में बुजुर्ग को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

80 कैमरों की मदद से तलाश कर बरामद किया बैग

अजमेर में एक महिला का बैग ई-रिक्शा में छूट गया। सूचना मिलते ही कांस्टेबल मनीष शर्मा ने करीब 80 सीसीटीवी कैमरों की मदद से रिक्शा का पता लगाया और बैग बरामद कर सुरक्षित महिला को लौटा दिया। सामान सही-सलामत मिलने पर महिला ने पुलिस का आभार जताया। ■

77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह

पुलिस के जवान प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्पर

राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के साथ हर परिस्थिति में ढ़ाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 77 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसालें पेश की हैं। उन्होंने अमर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया।

नवीन कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाए गए नवीन कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26, लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने की घोषणा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों के निर्माण की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर एवं उत्सव फंड को मजबूत करने के लिए 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पुलिस कर्मियों के आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों के निर्माण की भी घोषणा की गई। ■

नगाड़ों-शहनाइयों के बीच जीवंत हुआ

गणगौर उत्सव

जयपुर में 21 मार्च को आयोजित गणगौर महोत्सव की राजसी सवारी ने पूरे शहर को लोक संस्कृति और आस्था के रंग में रंग दिया। सिटी पैलेस से रवाना हुई सवारी के साथ भारी जनसैलाब उमड़ा और त्रिपोलिया गेट से गणगौरी बाजार तक लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। सजी-धजी पालकियों में विराजीं गणगौर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उमड़े। नगाड़ों, शहनाई और जयकारों के बीच 210 लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी, गैर, कालबेलिया, चरी और घूमर जैसे लोकनृत्यों से माहौल को जीवंत बना दिया। 32 पारंपरिक लवाजमों, सुसज्जित हाथियों, ऊंटों, घोड़ों, विक्टोरिया कैरिज और विभिन्न बैंडों, विशेषकर पहली बार शामिल शंकर बैंड ने शोभायात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया।

रील इज रियल

केन्द्रीय और राज्य बजट ने ऑरेंज इकोनॉमी को दिया बड़ा बूस्ट

वर्ष 2030 तक 20 लाख प्रशिक्षित युवाओं को मिलने लगेंगे इस सेक्टर में रोजगार के अवसर

ब्रजेश कुमार सामरिया, उपनिदेशक

क्या है ऑरेंज इकोनॉमी?

ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां मूल्य भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि विचारों, ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्ति से उत्पन्न होता है। इसका एक प्रमुख हिस्सा 'कंसर्ट इकोनॉमी' है, जिसमें बड़े स्तर के लाइव संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ-साथ हॉस्पिटिलिटी, ट्रैवलिंग, टिकट बिक्री, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, विज्ञापन और स्थानीय सेवाएं भी शामिल होती हैं।

केंद्र और राजस्थान के वर्ष 2026-27 के बजट ने देश में क्रिएटिव टैलेंट मूवमेंट को नई दिशा दी है। केन्द्रीय बजट में मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) द्वारा देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में आवश्यक 20 लाख पेशेवरों की मांग को पूरा करना है। वहीं, राजस्थान बजट 2026-27 की ड्रीम (डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग) योजना इस दिशा में एक मजबूत पूरक के रूप में सामने आई है, जिसके तहत प्रथम चरण में लगभग 50 हजार विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता से आगे बढ़ाकर डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाएगा।

ऑरेंज इकोनॉमी में बढ़ती संभावनाएं और निवेश

क्रिएटिव इंडस्ट्री, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है, तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। वर्ष 2008 में आई 'छोटा भीम' के पात्रों पर आधारित कैफे चेन शुरू होने जा रही है, जो कंटेंट से कमर्शियल विस्तार का उदाहरण है। इसी तरह नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' फिल्म में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वीएफएक्स, एआई डबिंग और संगीत जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों पर खर्च किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि एवीजीसी और डिजिटल कंटेंट सेक्टर न केवल रोजगार सृजन कर रहा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है।

एवीजीसी सेक्टर पर प्रधानमंत्री का विजन और वैश्विक अवसर

इस सेक्टर की महत्ता को समझने के लिए 12 जनवरी, 2026 का संदर्भ महत्वपूर्ण है, जब भारत मण्डपम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय एवीजीसी उद्योग से इस उभरते वैश्विक क्षेत्र की अपार संभावनाओं को अवसर के रूप में स्वीकार करने और उसमें अग्रणी बनने का आह्वान किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बजरंगबली जैसे भारतीय चरित्र अकेले ही मारियो, हीमैन या सुपरमैन जैसे वैश्विक पात्रों के संयुक्त दर्शकों, पाठकों और गेम प्लेयर्स से अधिक लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्पष्ट विजन है कि भारत को एवीजीसी उद्योग में केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व स्थापित करना है।

वैश्विक गेमिंग उद्योग और भारतीय संस्कृति की संभावनाएं

भारत के पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत के पात्रों में इतनी गहराई और विविधता है कि वे मिकी माउस, मारियो या पिकाचू जैसे अंतरराष्ट्रीय पात्रों को प्रभावी रूप से चुनौती दे सकते हैं।

लोककथाओं से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तार

भारत के लाखों गांवों और हजारों महलों-किलों में फैली अनगिनत कहानियां चाहे वे दु:खान्त हों या सुखान्त... प्रेम, वीरता, त्याग या बलिदान से जुड़ी ये कहानियां क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों को एनिमेशन, गेमिंग, फिल्मों और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए रोमांचक और आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे न केवल मनोरंजन के नए आयाम खुलेंगे, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान भी मिलेगी।

सॉफ्ट पावर में गेमिंग की नई भूमिका

वर्तमान दौर में संचार केवल अर्थव्यवस्था और प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के सशक्तीकरण, विकसित भारत@2047 के लक्ष्य और भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर में अध्यात्म, बुद्ध, गांधी, आयुर्वेद, गंगा, अहिंसा और योग के साथ अब गेमिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।

ऑरेंज इकोनॉमी का बढ़ता आर्थिक प्रभाव

देश में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र निरंतर विस्तार की राह पर है, जिसमें वर्ष 2027 तक राजस्व लगभग 7 प्रतिशत सालाना बढ़ने का अनुमान है। भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का आकार वर्ष 2024 के 2,502 अरब रुपये से बढ़कर 2027 में 3,067 अरब रुपये होने का अनुमान है, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक टिकाऊ विकास इंजन के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

भारत में कंसर्ट इकोनॉमी की उभरती संभावनाएं

पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में कंसर्ट इकोनॉमी अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन युवा आबादी, बढ़ती आय, डिजिटल टिकटिंग प्लेटफॉर्म और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के कारण यह तेजी से विकसित हो रही है। युवाओं की अधिकता के चलते भारत भविष्य में इसका स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बन सकता है, क्योंकि यही वर्ग मुख्य रूप से क्रिएटर और उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र की सफलता के लिए सुव्यवस्थित अनुमतियां, स्पष्ट नियम, प्रभावी भीड़ प्रबंधन, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत प्रशासनिक समन्वय अत्यंत आवश्यक हैं। इसी दिशा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसने कम समय में देशभर के संबंधित हितधारकों को एक उच्च स्तरीय सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

अगला चरण 'पर्यटन और आतिथ्य'

आतिथ्य उद्योग विश्व के सामने देश की छवि गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन क्षेत्र प्रति रुपये या डॉलर के निवेश पर विनिर्माण या सेवा सेक्टर की तुलना में अधिक रोजगार सृजित करता है। यह विशेष रूप से युवाओं तथा अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए अवसर प्रदान करता है। यह पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सक्षम उद्योग माना जा सकता है।

पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म को बजट से नई गति

भारत अपने अजंता-एलोरा, अयोध्या-वाराणसी और ताजमहल-लाल किला जैसे विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है और इनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय बजट 2026-27 महत्वपूर्ण पहल लेकर आया है। इस बजट के तहत 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षित करने, वन्यजीव, ट्रेकिंग और प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। साथ ही, 3 आयुर्वेद एम्स और 5 क्षेत्रीय आयुष मेडिकल हब की स्थापना से मेडिकल टूरिज्म को नई गति मिलेगी। किफायती उपचार और उच्चतम मानकों के कारण भारत पहले से ही मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित वैश्विक गंतव्य है और ये पहल इसकी इस पहचान को और मजबूत करेंगी। ■

" प्रदेश में एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है। माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेट क्रियेटर लैब्स की स्थापना से, राजस्थान के युवाओं को दोहरा लाभ होगा।"

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति

सहकारिता से सुदृढ़ हो रहा भण्डारण तंत्र

सहकारी समितियों को मिल रही मजबूती, कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार

दिनेश शर्मा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

कृषि और पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। इन क्षेत्रों की मजबूती के लिए भण्डारण सुविधाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। यह पहल न केवल किसानों को उनकी उपज सुरक्षित रखने में मदद कर रही है, बल्कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बना रही है।

किसान विषम परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत कर सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन मौसम की बेरूखी और भण्डारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक देश में 30 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान इस योजना को क्रियान्वित करने में देश में अग्रणी है।

राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है, जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए शत–प्रतिशत (25 लाख रुपये प्रति गोदाम) अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के साथ ही 250 मीट्रिक टन एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही, वर्ष 1990 से पूर्व निर्मित ऐसे गोदाम जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहे, का भी पुनर्निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य बजट 2024-25 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए प्रति समिति 25 लाख रुपये के अनुसार कुल 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इनमें से 92 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण के लिए प्रति समिति 12 लाख रुपये की दर से 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 31 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

इसी प्रकार, राज्य बजट वर्ष 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 एवं 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों के निर्माण के लिए 33 करोड़

रुपये का प्रावधान किया गया। इनमें से 500 मीट्रिक टन क्षमता के सभी 100 गोदामों के स्वीकृति आदेश जारी कर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं। जबकि, 250 मीट्रिक टन क्षमता के भी सभी 50 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण के लिए भी 12 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रावधान के विरूद्ध भी सभी समितियों का चयन किया जाकर निर्माण प्रक्रियाधीन है।

राज्य बजट 2026-27 में भी 500 मीट्रिक टन एवं 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50-50 गोदामों के निर्माण की घोषणा की गई है। इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के जीर्ण-शीर्ण गोदामों में चारदीवारी के पुनर्निर्माण पर 15 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 200 नवगठित गोदामविहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं कार्यालय भवन मय चारदीवारी निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की गई है।

100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम कार्यालय भवन एवं गोदाम पैटर्न पर बनाये जाते हैं, जिससे एक ओर जहां नवीन समितियों को कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध हो जाता है वहीं दूसरी ओर खाद, बीज एवं कृषि आदानों के भण्डारण इत्यादि की भी सुविधा मिलती है। वहीं, 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में किसानों को भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ समितियों की आर्थिक सक्षमता को बढ़ाना भी है। समितियों द्वारा इन गोदामों का विविध रूप में उपयोग किया जा रहा है। कुछ गोदामों को समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ गोदामों में सीड ग्रेडिंग यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इन गोदामों को प्राथमिकता से किराये पर लिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं नैफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा भी सरकारी विभागों/संस्थाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ गोदामों को निजी क्षेत्र को भण्डारण हेतु किराये पर दिये जाने का विकल्प खुला रखा है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई है।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्थाओं को मजबूती मिल रही है। किसानों को अपनी उपज के सुरक्षित भण्डारण की सुविधा मिलने से उन्हें तत्काल बिक्री के दबाव से राहत मिलती है और वे अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था उपलब्ध होने से अनाजों की ढुलाई में आने वाली लागत कम होगी। नये गोदामों के निर्माण से अनाज की बर्बादी रूकेगी। साथ ही, इन गोदामों को किराये पर दिए जाने से सहकारी समितियों की आय में वृद्धि होगी। ■

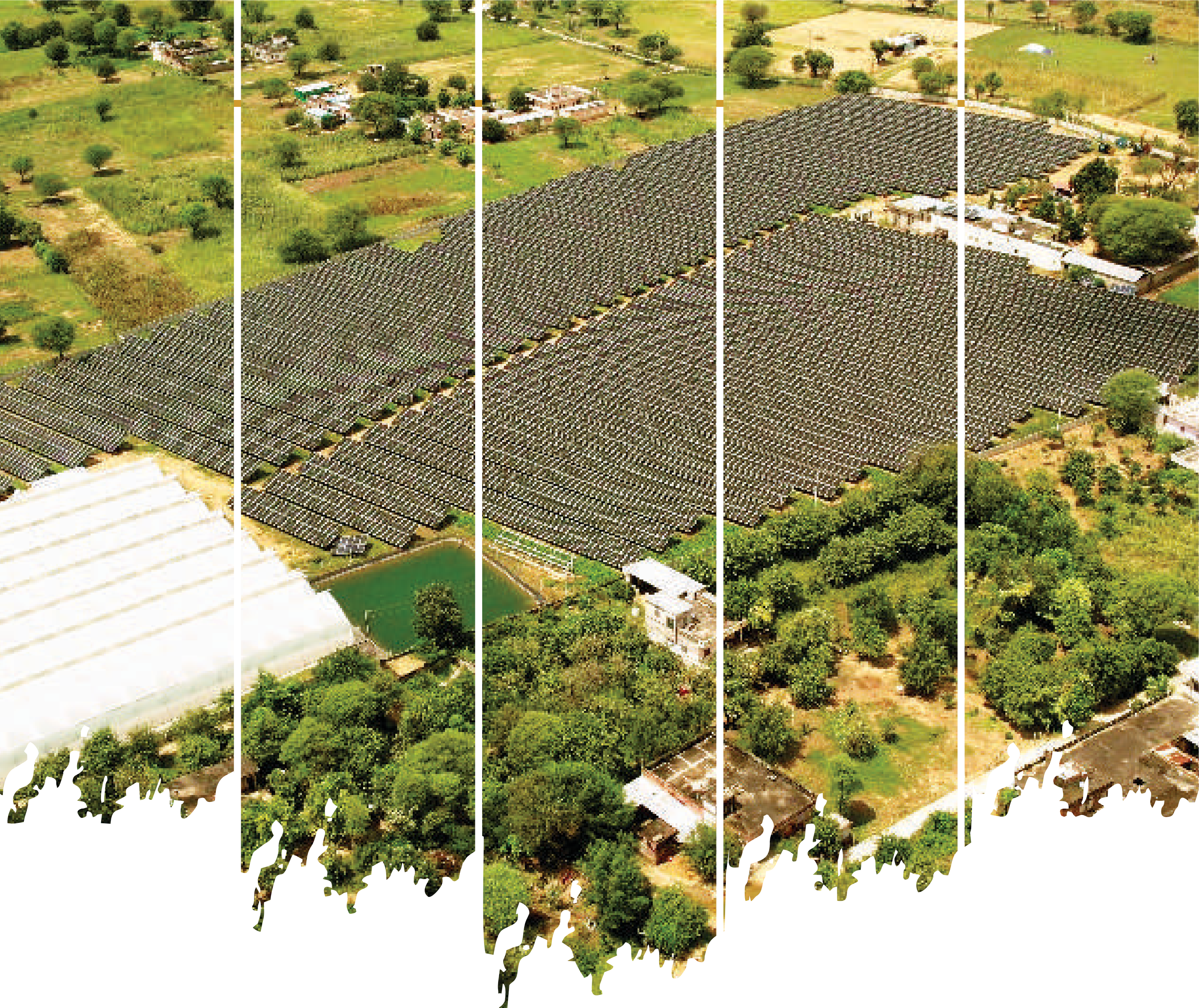

सूरज से पैदा हो रही बिजली खेत से निकल रहा सोना

अभिषेक कुमार जैन, उपनिदेशक

दूर तक फैले रेतीले धोरे। हरियाली का कोई नामोनिशान नहीं। तीक्ष्ण किरणें बिखेरता सूरज और तपती मरूधरा। मन-मस्तिष्क में यही तस्वीर उभरती थी राजस्थान की। लेकिन, स्थिति अब बदल चुकी है। जहां तक नजर जाती है, हरे-भरे खेत और दमकते नीले सोलर पैनल दिखाई पड़ते हैं।

> प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किसान-कल्याण के संकल्प से प्रेरित होकर हम निरंतर किसानों के जीवन को आसान और समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की है। हर घर-हर खेत को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, प्रतिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। आज 24 जिलों में किसानों को दिन में, बिजली मिल रही है और राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेशभर में, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराएगी। किसान समृद्ध होंगे, तभी राजस्थान विकसित होगा।
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण पहल पीएम-कुसुम योजना में लग रहे ग्रिड कनेक्टेड विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों ने प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। इन संयंत्रों से उत्पन्न बिजली से किसानों का दिन में सिंचाई का सपना साकार हो रहा है। गांव-ढाणी और घर रोशन हो रहे हैं। खेत- खलिहान हरे-भरे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। सही मायनों में अन्नदाता अब ऊर्जादाता और भाग्य विधाता बन गया है। इससे कोयले से उत्पन्न बिजली पर निर्भरता कम हुई है और सस्ती एवं प्रदूषणरहित सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि में बढ़ा है।

प्रोत्साहन तथा व्यापक जनभागीदारी

राजस्थान के गांव-ढाणी में कुसुम कंपोनेंट-ए एवं कंपोनेंट-सी में अब तक 3857 मेगावाट के 1744 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 3735 मेगावाट के 1652 संयंत्र वर्तमान सरकार के अब तक के करीब ढाई वर्ष के कार्यकाल में स्थापित हुए हैं। यह आंकड़े मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस योजना को दिए जा रहे प्रोत्साहन तथा व्यापक जनभागीदारी से प्राप्त सफलता को दर्शाते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

कुसुम कम्पोनेंट-ए में 756 मेगावाट के 538 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं कम्पोनेंट-सी में 3101 मेगावाट के 1206 प्लांट लग चुके हैं। इसमें राजस्थान का द्वितीय स्थान है। योजना में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने इसी वर्ष जनवरी माह में दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया था।

श्री शर्मा ने वर्ष-2027 तक प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली से प्रदेश में 2 लाख 50 हजार से अधिक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ हो रही है।

विगत समय में प्रदेश में कुसुम प्लांटों के स्थापित होने की गति और तेज हुई है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में औसतन तीन से चार नए प्लांट प्रतिदिन लग रहे हैं। जिनसे औसतन 10 मेगावाट क्षमता प्रतिदिन ग्रिड से अतिरिक्त जुड़ रही है। इस वर्ष जनवरी माह में ही 286 मेगावाट तथा फरवरी माह में 295 मेगावाट क्षमता के प्लांट ग्रिड से जुड़ चुके हैं। कम्पोनेंट-ए में सर्वाधिक 86 प्लांट अकेले बीकानेर जिले में स्थापित हुए हैं। इसके पश्चात् 34 सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में तथा 32 सौर संयंत्र झुंझुनूं सर्किल में लग चुके हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में फलौदी में 24,561, जोधपुर में 22,469 तथा बीकानेर में 22,003 सोलर पंपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है।

त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित

कुसुम योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगम लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करने, सोलर प्लांट स्थापित करने तथा पावर परचेज एग्रीमेंट करने से संबंधित प्रक्रियाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। एसओपी में निहित प्रावधानों के अनुरूप मीटर टेस्टिंग, ट्रांसमिशन लाइनें डालने तथा ट्रांसफार्मर से संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाता है।

बिजली वितरण हुआ आसान

कुसुम योजना में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां तथा सौर ऊर्जा उत्पादक स्वयं अथवा लीज पर भूमि लेकर अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादक अपने संयंत्रों से उत्पादित बिजली वितरण निगमों को खरीद अनुबंध के माध्यम से निर्धारित दर पर उपलब्ध करा रहे हैं। पैदा हो रही बिजली का उपयोग उसी सब स्टेशन पर होने से विद्युत निगमों को अलग से वितरण अथवा प्रसारण तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे वितरण लॉसेज भी न्यूनतम होते हैं, जिसका लाभ वितरण निगमों को मिलता है।

सौर ऊर्जा से बदली तस्वीर

कुसुम योजना में लग रहे सौर ऊर्जा संयंत्रों से डेढ़ हजार से अधिक नए सोलर उद्यमी ऊर्जा उत्पादन से जुड़ चुके हैं। उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत मिला है। इससे उनके आर्थिक जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुपजाऊ भूमि का उपयोग सुनिश्चित हुआ है और देश की ऊर्जा सुरक्षा में सर्वसुलभ सौर ऊर्जा का योगदान बढ़ा है। ■

संवाद सुनवाई समाधान

अनसुनी नहीं रहेगी अब कोई शिकायत 181 पर पाएं तुरंत राहत

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय स्थित, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन-181 का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने आमजन से सीधे संवाद कर समस्याएं जानीं और निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर, धरातल पर पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो। वरिष्ठ अधिकारियों विशेषकर एसीएस और शासन सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी समय-समय पर स्वयं संपर्क पोर्टल जाकर आमजन की कॉल सुनते हैं और मौके पर निर्णय लेते हैं।

हाल ही 3 अप्रैल को जब सीएम श्री शर्मा संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन पर फोन कॉल्स पर परिवेदनाएं सुन रहे थे, तो उस दौरान जयपुर निवासी ज्योति की एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी नागरिक असंतुष्ट न रहे तथा प्रत्येक परिवेदना का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निस्तारण किया जाए।

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

एक डायल पर समाधान

सुनवाई से समाधान तक

जवाबदेह शासन की जिम्मेदारी पर खरी उतरती राजस्थान सरकार

जयेश पण्डया, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

इन तरीकों से नागरिक दर्ज करा सकते हैं अपनी समस्याएं और शिकायतें

वेबसाइट : sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से

मोबाइल ऐप राजस्थान सम्पर्क 2.0 के जरिए

व्हाट्सएप नम्बर +91 9461067924 पर

टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करके

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह आम नागरिक की शिकायतों को कितनी गंभीरता और कितनी तत्परता से सुनती है। प्रदेश में हाल के महीनों में राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, ये केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि शासन की सोच और कार्य-संस्कृति में प्रगति का साफ संकेत हैं।

सुधार से सुदृढ़ता तक

बीते वर्षों में शिकायत निवारण की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। शिकायतें दर्ज तो होती थीं, लेकिन उनके जमीनी स्तर पर त्वरित और प्रभावी निस्तारण को और सशक्त बनाने की जरूरत थी। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विशेष पहल के बाद जो परिदृश्य उभरकर सामने आया है, वह प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इससे आमजन के बीच शिकायत निवारण तंत्र के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

तेजी और गुणवत्ता का संगम

एक ही दिन में 25 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण, औसत समाधान समय का 14 दिन से घटकर 7 दिन होना और संतुष्टि स्तर का 80 प्रतिशत से अधिक पहुंचना ये आंकड़े अपने आप में इस अभूतपूर्व बदलाव की गंभीरता को दर्शाते हैं। उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल, 2026 को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) पर दैनिक शिकायत निस्तारण का 'आल टाइम हाई लेवल', 28 हजार 901 प्रकरण दर्ज किया गया था। इस दिन दर्ज शिकायतें सिर्फ 13 हजार 605 थीं, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

सीधा संवाद, त्वरित समाधान

इस परिवर्तन के केंद्र में मुख्यमंत्री श्री शर्मा की स्पष्ट प्राथमिकता है, जिसमें शिकायत निवारण को शासन का केन्द्रीय तत्व माना गया है। अब यह अप्रत्याशित रूप से आम है कि प्रदेश का कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवाने 181 पर कॉल करे और सामने फोन पर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री परिवेदना सुन रहे हों। मुख्यमंत्री अक्सर स्वयं सम्पर्क पोर्टल का अवलोकन करते हैं और आमजन की परिवेदनाएं सुनते हैं, जिनके तत्काल समाधान से आमजन के बीच उत्तरदायी शासन का गहरा संदेश पहुंचता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ ही विभिन्न विभागों के मंत्री भी हेल्पलाइन पर आमजन की शिकायतें सुनते हैं।

राजस्थान सम्पर्क 181

प्रशासनिक समन्वय से मिली गति

इस बदलाव और इसके सकारात्मक परिणामों को सतत रूप से प्राप्त करने हेतु केवल शीर्ष स्तर की इच्छाशक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसे जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के साथ ही उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता होती है। मुख्य सचिव के स्तर से इस पूरी प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग, विभागों के साथ समन्वय और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों ने इस अभियान को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप गति प्रदान की है।

17 अप्रैल 2026	शिकायत निस्तारण	दर्ज शिकायतें
	28,901	13,605

सख्त मॉनिटरिंग से तेज हुआ समाधान तंत्र

नियमित समीक्षा बैठकों, विभागवार प्रगति की निगरानी और लंबित मामलों पर सख्त निर्देशों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि संपर्क पोर्टल केवल एक हेल्पलाइन न रहकर एक एक्शन प्लेटफॉर्म बने। वरिष्ठ अधिकारियों विशेषकर एसीएस और शासन सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को सीधे इस प्रक्रिया में शामिल करना भी इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। जब समय-समय पर प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी स्वयं संपर्क पोर्टल जाकर आमजन की कॉल सुनते हैं और मौके पर निर्णय लेते हैं, तो इससे न केवल प्रक्रिया तेज होती है, बल्कि पूरे तंत्र में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि अब जवाबदेही से बचना संभव नहीं है।

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इन प्रयासों ने शासन की उस पुराने व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जहां शिकायतें अक्सर फाइलों में दबकर रह जाती थीं। अब यदि एक आम नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी समस्या सीधे शीर्ष स्तर तक पहुंच सकती है और उसका समाधान भी संभव है, तो यह लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंततः राजस्थान संपर्क पोर्टल का यह परिवर्तित स्वरूप महज शासन-प्रशासन की एक पहल की सफलता नहीं, बल्कि उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जिसने शासन को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ■

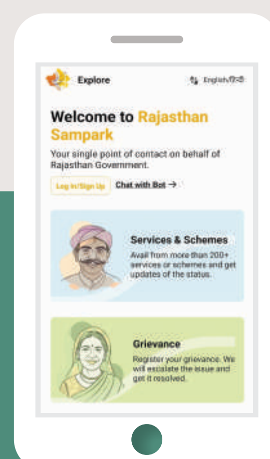

Rajasthan Sampark 2.0

नारी शक्ति से कृषि सशक्तीकरण

आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी

अमन हरसाना, स्वतंत्र लेखक

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि ने राष्ट्रीय आय, रोज़गार सृजन और ग्रामीण आजीविका में बड़ा योगदान दिया है। देश की लगभग 46.1 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़े कार्यकलापों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, और डेयरी जैसे क्षेत्र आजीविका के मुख्य स्रोत हैं, जिसमें 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं संलग्न हैं। इनमें से 33 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं और 48 प्रतिशत स्वरोजगार वाली किसान हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष (IYWF 2026) घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने, भूमि, संसाधनों, प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजारों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह वर्ष सरकारों, विकास साझेदारों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र को समावेशी नीतियों और लक्षित कार्यवाहियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है जो महिला किसानों की दृश्यता, मान्यता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाए।

महिला किसान सशक्तीकरण सुनिश्चित करती योजनाएं

नमो ड्रोन दीदी योजना

15 अगस्त, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई "नमो ड्रोन दीदी" योजना 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू की जा रही है, जिसके तहत 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देना, कार्य दक्षता बढ़ाना और SHGs को ड्रोन-आधारित सेवाएं उपलब्ध कराकर महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाना है। चयनित SHGs को ड्रोन पैकेज पर 80 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (अधिकतम 8 लाख रुपये) दी जाती है, साथ ही ड्रोन पायलट के लिए 15 दिनों का प्रशिक्षण और ड्रोन सहायक के लिए 5 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। योजना के तहत ड्रोन प्राप्त करने के लिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा, प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को नैनो यूरिया/डी.ए.पी. के ड्रोन छिड़काव पर, 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना की अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://namodronedidi.da.gov.in/ पर ली जा सकती है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना

कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गई यह योजना कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाओं और उत्पादक फार्म संपत्तियों के विकास के लिए ऋणों पर ब्याज सबवेंशन और ऋण गारंटी समर्थन के माध्यम से मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य ध्यान फार्म गेट पर भंडारण और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना बनाने, किसानों को अपनी उपज को ठीक से संग्रहीत करने, कटाई के बाद नुकसान कम करने और बिचौलियों पर निर्भरता सीमित करके बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने पर है। एआईएफ के तहत ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा 9 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत एक ही स्थान पर प्रति परियोजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी, सात वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाती है। अभी तक, योजना के तहत महिला किसानों को 8,190 परियोजनाओं के तहत 2,377 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://agriinfra.dac.gov.in/ पर विजिट किया जा सकता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

यह कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं के माध्यम से लागू किया जाता है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करने, महिलाओं को स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी अवसर प्रदान करके सतत, विविधीकृत आजीविकाएं सृजित करता है। योजना के तहत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से महिला SHGs को 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच, 2.58 करोड़ महिला किसानों को एग्रो-इकोलॉजी और पशुपालन प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया, 2.50 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जैसे पशु सखियां प्रशिक्षित की गईं, 503 कृषि सखियां ड्रोन सखी के रूप में प्रशिक्षित की गईं, 70,021 SHG महिलाओं को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण दिया गया तथा FPO योजना के तहत 800 महिला-नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियां प्रोत्साहित की गईं। अधिक जानकारी के लिए https://nrlm.gov.in/ पर विजिट किया जा सकता है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्रमुख उप योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला किसानों को कृषि, आजीविका और सतत खेती के क्षेत्र में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। अधिक जानकारी https:// mksp.nrlm.gov.in/portal/ पर ली जा सकती है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM-KISAN योजना का उद्देश्य भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिए जाते हैं। राजस्थान बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 3,000 रुपये देने से कुल सहायता 9,000 रुपये हो गई है। किसान इस योजना में PM-KISAN पोर्टल, मोबाइल ऐप और CSC के जरिए

पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन किया जाता है। विश्व के सबसे बड़े DBT कार्यक्रमों में से एक PM-KISAN ने किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करके महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उल्लेखनीय रूप से, कुल लाभों का लगभग 25 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को जाता है, जो महिला किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

किसान सामूहिकता को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने 29 फरवरी, 2020 को '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन' परियोजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य उत्पादन और विपणन में पैमानें की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने, उत्पादन लागत में कमी लाने और उनके कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम बनाना है, जिससे नियमित रूप से आमदनी की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा सके। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को एफपीओ प्रबंधन के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक का इक्विटी अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसकी सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये है और पात्र ऋणदाता संस्था से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की गई है, ताकि एफपीओ को संस्थागत ऋण की सुलभता सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक FPO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक महिला सदस्य है, और महिला-केंद्रित FPOs की मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति है, जिसमें 1,175 FPOs में 100 प्रतिशत महिला शेयरधारक हैं और 1,084 FPOs में 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत महिला सदस्य हैं।

कृषि सखियां

कृषि सखियां व्यावहारिक महिला किसान हैं, जो प्राकृतिक खेती और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन में सतत कृषि का समर्थन करने के लिए पैरा-विस्तार पेशेवर के रूप में प्रशिक्षित हैं। वे "किसानों की सहेलियां" के रूप में कार्य करती हैं, जो घर-द्वार पर मार्गदर्शन, ज्ञान और समर्थन प्रदान करती हैं। सामुदायिक-आधारित विस्तार को मजबूत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से 70,000 कृषि सखियों का प्रशिक्षण संयुक्त रूप से आरंभ किया है। प्रशिक्षण के बाद, कृषि सखियां SHGs, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, ग्राम पंचायतों और ग्राम संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीण महिला किसानों को विस्तार सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर कृषि सखियां भागीदारी मजबूत करने, कौशल सुधारने और कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)

वर्ष 2005-06 से देश में विकेंद्रीकृत और किसान हितैषी विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना राज्य सरकार के विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का समर्थन करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को किसानों, कृषि महिलाओं और युवाओं को किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेलों आदि जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में विकेंद्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। यह फार्म महिला खाद्य सुरक्षा समूहों (FSGs) का समर्थन करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती है, जो रसोई बागवानी, बैकयार्ड मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती तथा डेयरी गतिविधियों के माध्यम से 'मॉडल खाद्य सुरक्षा हब' के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक FSG को प्रशिक्षण, प्रकाशनों और आवश्यक इनपुट्स के लिए 25,000 रुपये मिलते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में प्रति वर्ष कम से कम दो समूह गठित किए जाते हैं। ATMA के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या 2024-25 में 9.93 लाख से बढ़कर 2025-26 में 11.61 लाख हो गई, जो लगभग 16.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

भारत, जो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है, के लिए दलहन मिशन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर, 2025 को 2025-26 से 2030-31 तक 11,440 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन विशेष रूप से अरहर, उड़द और मसूर पर केंद्रित है तथा जलवायु-प्रतिरोधी बीज, खेती के क्षेत्र विस्तार और भंडारण व प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देता है। साथ ही, NAFED और NCCF के माध्यम से PM-AASHA के तहत इन दालों की सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था की गई है और राज्यों को कम से कम 20 प्रतिशत फंड महिला किसानों के लिए सुनिश्चित करना होता है। राजस्थान में इस मिशन के तहत 2.45 लाख क्विंटल दलहन बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 79 नई दलहन किस्मों की पहचान कर उन्हें तेजी से सीड चेन में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा, दलहन प्रोसेसिंग को मजबूत करने के लिए राजस्थान में 30 दाल मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय सहायता के तहत वर्ष 2026–27 के लिए राज्य को 312 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, साथ ही अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की शत-प्रतिशत उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर आय और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तीकरण योजना

यह योजना राजस्थान सरकार के कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषि उत्पादन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उपज के विपणन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में महिलाओं द्वारा कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई-भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई है, ताकि महिला कृषकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना

राजस्थान सरकार की इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके तहत महिला श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूतियों तक 45 दिनों की मजदूरी के बराबर प्रसूति सहायता और पिता को 15 दिनों की मजदूरी के बराबर पितृत्व सहायता दी जाती है। विवाह सहायता के रूप में अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक या उसकी अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर 75,000 रुपये प्रति विवाह प्रदान किए जाते हैं। साथ ही, 10वीं, 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को 2 हजार रुपये से लेकर 6 हजार 500 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा, कैंसर, हृदय, लीवर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 20,000 रुपये तक की चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan/ पर विजिट किया जा सकता है।

किसान कलेवा योजना

राजस्थान सरकार की इस योजना का उद्देश्य मण्डी प्रांगण में कृषि उपज बेचने आने वाले किसानों तथा अनुज्ञापत्रधारी हम्माल, पल्लेदार और तुलारों को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना श्रमिकों और किसानों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य एवं सुविधा को सुनिश्चित करती है। योजना के अंतर्गत मात्र रुपये 5 प्रति व्यक्ति की दर से संतुलित भोजन थाली उपलब्ध कराई जाती है। थाली में 8 चपाती (250 ग्राम आटा), एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, सर्दियों में 50 ग्राम गुड़ (अक्टूबर से मार्च) तथा गर्मियों में 200 मि.ली. छाछ (अप्रैल से सितंबर) शामिल होती है।

आत्मनिर्भर और विकसित भारत व राजस्थान के निर्माण में महिला किसानों की भागीदारी न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बना रही है, बल्कि ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक समानता को भी नई दिशा देने का काम कर रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता, तकनीकी ज्ञान, बाजार तक पहुंच और संस्थागत समर्थन प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनका समग्र सशक्तीकरण सुनिश्चित हो रहा है। ■

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

(2025-26 to 2030-31)

- वर्ष 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- इस मिशन पर सरकार 11,440 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
- लगभग 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीज, भंडारण सुविधाएं और उपज की सुनिश्चित खरीद से सीधा लाभ मिलेगा।
- नई एवं उन्नत किस्मों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे।
- फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- आगामी 4 वर्षों तक सरकार तूअर, उड़द और मसूर की पूरी उपज किसानों से खरीदेगी।

स्कैन कर हमें फॉलो करें

किसान कॉल सेंटर

1800-180-1551 (6 AM - 10PM)

@agrigoi

पशुपालकों को मिल रहा

आर्थिक आधार

डूंगरपुर जिले में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से वित्तीय संबल

छाया चौबीसा, सहायक निदेशक

ग्रामीण जीवन की आधारशिला पशुपालन है, जो न केवल आजीविका का प्रमुख साधन है, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने वाला एक सशक्त स्तंभ भी है। वर्तमान समय में दुधारू पशुओं की बढ़ती कीमतों ने पशुधन के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है, वहीं किसी पशु की आकस्मिक मृत्यु पशुपालक परिवार के लिए गहरे आर्थिक और मानसिक आघात का कारण बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पशुधन की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि शासन की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। इसी दायित्व को संवेदनशीलता के साथ निभाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट सहित लगभग 42 लाख पशुओं का नि:शुल्क बीमा सुनिश्चित किया जा रहा है। यह पहल न केवल पशुपालकों को आकस्मिक हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

डूंगरपुर जिले में योजना की प्रभावी क्रियान्विति

राजस्थान के सुदूर दक्षिण में अरावली पर्वतमाला की उपत्यकाओं के बीच स्थित 'पहाड़ों की नगरी' के रूप में प्रसिद्ध डूंगरपुर जिले में यह योजना पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जनजाति बहुल इस क्षेत्र में सिंचाई संसाधनों की सीमित उपलब्धता, वर्षा आधारित कृषि, पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियां तथा छोटी जोत के कारण कृषि के साथ-साथ पशुपालन यहां के निवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार बना हुआ है। जिले में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन पशुपालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और उनके जीवन में सुरक्षा एवं स्थिरता का भाव उत्पन्न कर रहा है।

पशुधन सुरक्षा से सशक्त हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पशुपालन विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर सर्वे एवं पंजीकरण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत घर-घर, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंच बनाई गई। इसके परिणामस्वरूप प्रथम चरण में 32,766 पशुओं का बीमा करते हुए 99 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। इस योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में अब तक 919 पशुपालकों के खातों में कुल 1 करोड़ 8 लाख 97 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित कर उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है। योजना से प्राप्त इस सहयोग ने पशुपालकों को न केवल आर्थिक राहत दी है, बल्कि उनके जीवन में संतोष और सुरक्षा का भाव भी उत्पन्न किया है, जो उनके चेहरे पर सहज ही परिलक्षित होता है।

पशु बीमा को मिली गति

योजना के द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 43200 पशुओं का बीमा किए जाने का लक्ष्य का आवंटन किया गया है, जिसमें दुधारू गोवंश-8200, दुधारू भैंस वंश-10700, भेड़ वंश- 4000, बकरी वंश-19000, उष्ट्र वंश 1300 सम्मिलित हैं। इसमें अप्रैल माह के आरम्भ तक लगभग 14855 पशुपालकों के 35522 पशुओं का पशु बीमा हेतु रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, उनमें से स्वस्थ पाए गए 23725 पशुओं का बीमा कर लिया गया है तथा 1693 पशुओं को पशु बीमा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बीमा विभाग द्वारा 22863 पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी कर दी गई है। वर्ष 2025-26 के 238 क्लेम प्रक्रियाधीन हैं।

पशुधन हानि पर गंगा देवी को मिला संबल

डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत ठाकरड़ा में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में गंगा देवी पाटीदार को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 28 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। पशुधन हानि के बाद प्राप्त इस आर्थिक सहयोग ने उनके जीवन में नई आशा का संचार किया। लाभार्थी गंगा देवी ने भावुक होकर ठेठ वागड़ी बोली में अपनी बात रखते हुए कहा "मरवा वारों सोपू तो पासू नी आवे, पण सरकार एणी योजना में जै पइसा आलवानु करूयू है ई घणु असल है, ऐने थकी अमे गरीब मनक बिजो सोपू फेर लावी संक ने, एने थकी अमारे घोर असल साली सके"। (मरने वाला पशु तो वापस नहीं आ सकता, परंतु सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता अत्यंत सराहनीय है। इससे हम गरीब लोग पुन: पशु खरीद सकते हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से कर सकते हैं।) यह उदाहरण दर्शाता है कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि संकट की घड़ी में पशुपालकों के लिए भरोसे और संबल का माध्यम भी बन रही है। ■

तारबंदी योजना

किसानों को अब मात्र 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी मिलेगा अनुदान

नेमीचन्द चौधरी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

अनुदान की प्रक्रिया

कांटेदार चेनलिंक तारबंदी योजना के अंतर्गत किसान द्वारा किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा उसका परीक्षण कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिसके बाद आवेदक किसान को तारबंदी कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात किसान अथवा समूह द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार खेत में तारबंदी का कार्य पूर्ण किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत व्यय से संबंधित सभी बिल एवं दस्तावेज संबंधित कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

इसके बाद अधिकारी द्वारा स्थल पर जाकर कार्य का भौतिक सत्यापन किया जाता है, जिसकी ऑनलाइन पुष्टि राज किसान साथी पोर्टल पर दर्ज की जाती है। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। यह योजना "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों का क्रमवार निस्तारण किया जाता है।

राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तारबंदी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे कृषकों की मांग को ध्यान में रखते हुए विभागीय दिशा-निर्देशों में परिवर्तन कर तारबन्दी में 1.5 हैक्टेयर भूमि की बाध्यता को दूर करते हुए इसे 0.5 हेक्टेयर किया गया है। यानी, अब मात्र 0.5 हेक्टेयर भूमि वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने में मदद मिलेगी। यह कदम न केवल कृषि सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आत्मनिर्भरता और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा देगा।

कांटेदार/चेनलिंक तारबंदी/वर्गाकार नोड फेंसिंग करवाने पर अनुदान

राजस्थान सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि और सीमांत व लघु किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से तारबंदी योजना के तहत अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की फसलों को नीलगाय व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना है, जो उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खेतों की कांटेदार, चेनलिंक अथवा नोड फेंसिंग पर अनुदान देकर सरकार न केवल फसल सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि किसानों को अधिक सुरक्षित एवं आत्मविश्वासपूर्ण कृषि करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे उनकी आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि संभव हो रही है।

योजना के लिए पात्रता व दिए जाने वाला अनुदान

कांटेदार/चेनलिंक तारबंदी/वर्गाकार नोडफेंसिंग योजना के लिए आवेदनकर्ता किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसके पास 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी आवश्यक है। यदि एक किसान के पास 0.5 हेक्टेयर नहीं है, तो वह अपने पड़ोसी के साथ मिलकर समूह में भी आवेदन कर सकता है। समूह में दो या दो से अधिक किसान मिलकर भी यदि 0.5 हेक्टेयर भूमि एक जगह पर रखते है, तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने हेतु सामुदायिक रूप से न्यूनतम 10 या अधिक किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते हैं, तो प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर 50 प्रतिशत या 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 40 हजार रुपये अनुदान राशि मिलेगी।

लघु एवं सीमांत किसानों को 400 मीटर लंबाई पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत या 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर पर 48 हजार रुपये तक प्रति कृषक देय होगा। वहीं सामूहिक रूप से 7 किसान मिलकर यदि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि तारबन्दी करते है तो उन्हें इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान अर्थात 140 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर पर 56 हजार रुपये प्रति किसान तक अनुदान देय है।

आवश्यक दस्तावेज

खेतों की तारबंदी पर अनुदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं पात्र किसानों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित भूमि की परिधि का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा (ट्रेस) एवं जमाबंदी, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड तथा लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसान स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसके उपरांत संबंधित विभाग द्वारा परीक्षण कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।■

आस्था, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम

सोनी जी की नसियां

पवन शर्मा, सहायक निदेशक

गौरवमयी इतिहास के लिए समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाले राजस्थान की धरा भौगोलिक वैविध्य, समृद्ध लोक कला एवं संस्कृति, उत्कृष्ट शिल्पकारी एवं प्राचीन स्थापत्य के विविध रंगों से भी श्रृंगारित है। यहां का बहुआयामी वैभव देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है । यहां के हर एक स्थल के प्राचीन इतिहास और कलात्मकता एवं संस्कृति की सौंधी सुगंध चहुं ओर बिखरी हुई है ।

भगवान श्री ऋषभदेव (आदिनाथ) की पूजा

जहां एक ओर राजस्थान के ऐतिहासिक नगर अजमेर के गौरवशाली इतिहास की अमर गाथा है, वहीं यहां का प्राचीन स्थापत्य वैभव भी अपने आप में अनूठा है। इसी का एक उदाहरण है – सोनी जी की नसियां। उन्नीसवीं सदी में निर्मित सोनीजी की नसियां उन्नत वास्तुकला एवं आकर्षक नक्काशी से न केवल राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, वरन सैलानियों व कलाप्रेमियों के लिये शोध एवं संदर्भ की दृष्टि से समृद्ध धरोहर है। श्री सिद्धकूट चैत्यालय के रूप में नामित यह स्थान पर्यटन के साथ ही आस्था का प्रमुख केन्द्र भी है। यहां 24 तीर्थंकरों में सबसे प्रथम भगवान श्री ऋषभदेव (आदिनाथ) की पूजा की जाती है। शोधार्थियों ने भी सोनीजी की नसियां को अजमेर के मुख्य आकर्षणों में से एक बताया है।

निर्माण एवं स्थापना

सोनी जी की नसियां का निर्माण वर्ष 1864 में मूर्धन्य पंडित सदा सुखदासजी के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा 26 मई 1865 को गर्भगृह में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के साथ इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस भव्य मंदिर का निर्माण अजमेर के प्रतिष्ठित व्यवसायी राय बहादुर सेठ मूलचंद एवं नेमीचंद सोनी द्वारा कराया गया, जिसके कारण इसे 'सेठ मूलचंद सोनी की नसियां' के नाम से भी जाना जाता है। लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण यह 'लाल मंदिर' के रूप में भी प्रसिद्ध है।

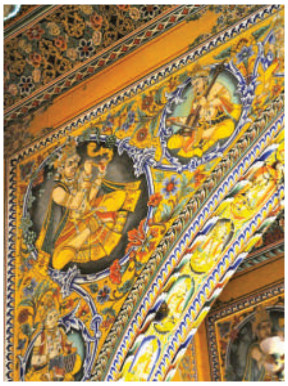

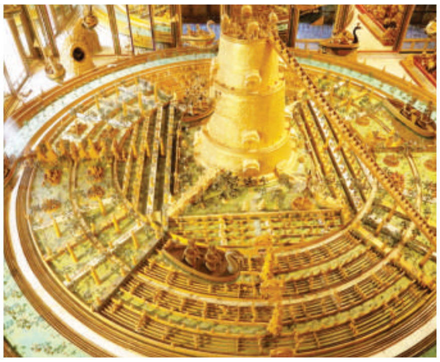

स्वर्ण नगरी हॉल की विशेषता

वर्ष 1895 में निर्मित इस मुख्य हॉल में जैन परंपरा से संबंधित स्वर्ण-पत्रयुक्त काष्ठ एवं ताम्र निर्मित कलाकृतियों का अद्भुत प्रदर्शन किया गया है। इसके अद्वितीय 'स्वर्ण नगरी' हॉल के कारण ही इसे 'सोने का मंदिर' कहा जाता है। यहां प्रदर्शित कलाकृतियों में स्वर्णिम गुम्बद, रथ, हाथी, स्तूप आदि पर अत्यंत सूक्ष्म एवं जटिल नक्काशी की गई है, जो उत्कृष्ट शिल्प कौशल का परिचायक है।

स्वर्ण नगरी का निर्माण एवं शिल्प कौशल

स्वर्ण नगरी का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। विशेष रूप से, आचार्य जिनसेन द्वारा एक प्राचीन पांडुलिपि के आधार पर भगवान ऋषभदेव की कथा पर आधारित त्रि-आयामी प्रतिकृति को साकार करने हेतु आवश्यक हजारों सूक्ष्म अवयवों को जयपुर के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया। इस जटिल एवं श्रमसाध्य कार्य को पूर्ण करने में वर्ष 1870 से 1895 तक लगभग पच्चीस वर्षों का समय लगा, जो उस काल की कला, धैर्य और तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उन्नत वास्तुकला का दिग्दर्शन

राजपूती मुगल शैली में निर्मित सोनी जी की नसियां में भगवान आदिनाथ के जीवन के पांच चरणों - पंच कल्याणक को इसके मॉडल और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये चरण हैं – गर्भ कल्याणक (गर्भाधान), केवल ज्ञान कल्याणक (सर्वज्ञता), जन्म कल्याणक (जन्म), तप कल्याणक (त्याग), और मोक्ष कल्याणक। मुख्य कक्ष को कलात्मक रूप से सोने और चांदी की कलाकारी और कीमती पत्थरों व प्राकृतिक रंगों पर आधारित आकर्षक चित्रकारी से सजाया गया है। हॉल में बेल्जियम स्टेन ग्लास, ठीकरी कांच शैली आधारित उन्नत व नयनाभिराम नक्काशी संग्रहालय के उत्कृष्ट कला-वैभव को दर्शाती है।

कलात्मक रूप से उत्कीर्ण जैन तीर्थंकरों के चित्र

इसके अलावा, यह स्थल दो भागों में विभाजित है, जहां एक भगवान आदिनाथ के प्रतीक से जुड़ा पूजा क्षेत्र है और दूसरा संग्रहालय है। करीब 10 हजार वर्गगज भूखंड पर निर्मित इन दोनों स्थलों के प्रबंधन का कार्य ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। मंदिर के पीछे की ओर "अयोध्या नगरी" है, जो अत्यंत आकर्षक एवं दर्शनीय है। यह पूरी तरह से स्वर्ण आच्छादित है। परिसर के बीच में एक 82 फीट ऊंचा स्तंभ निर्मित किया गया है, जिसे मानस्तंभ कहा जाता है। देश के जैन चैत्यालयों में स्थित स्तंभों में सबसे बड़े स्तंभ (मानस्तंभ) को जैन तीर्थंकरों के चित्र उत्कीर्ण कर इतने कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है कि दर्शक इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

सोनीजी की नसियां न केवल एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, वरन भव्य स्थापत्य कला और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आम जन के लिये पर्यटन का आकर्षक व मनोहारी स्थल भी है। इसकी भव्यता, शांति और ऐतिहासिक महत्त्व इसे एक अद्वितीय स्थल बनाते हैं। यह स्थल शिक्षा, शांति और अहिंसा के संदेश को प्रचारित करता है। यहां का पुस्तकालय भी यहां आने वाले शोधार्थियों के लिये ज्ञान एवं संदर्भ का अनमोल खजाना है। ■

पाती अपनों को मुहिम

विचार जो बन गया कारवां

डॉ. सूरज सिंह नेगी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा
प्रो. मीना सिरोला, वनस्थली विद्यापीठ

आज का समय भौतिक प्रगति और सुविधाओं के विस्तार का युग है, जहां जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है, किंतु इस विकास के समानांतर एक गंभीर सामाजिक चुनौती भी उभरकर सामने आई है। समाज में संवादहीनता और भावनात्मक शून्यता लगातार बढ़ रही है, रिश्तों की आत्मीयता क्षीण होती जा रही है और विशेष रूप से युवा पीढ़ी दिशाहीनता एवं दिग्भ्रम की स्थिति का सामना कर रही है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने लोगों को आभासी दुनिया में अधिक व्यस्त कर दिया है, जिसके कारण वे अपने ही परिवार और प्रियजनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, बल्कि एक सुदृढ़ परिवार, संवेदनशील समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है।

मुहिम की शुरुआत

अपनों को पुन: कैसे करीब लाया जाए, समाज में जीवन मूल्यों और सामाजिक सरोकारों के प्रति रुचि कैसे विकसित की जाए, युवा पीढ़ी को रचनात्मक दिशा में कैसे प्रेरित किया जाए तथा बढ़ती संवादहीनता को किस प्रकार कम किया जाए? ये आज के समय के अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंतनीय प्रश्न हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता समाज के प्रत्येक स्तर पर महसूस की जा रही है। इन्हीं प्रश्नों के समाधान की दिशा में लुप्त होती पत्र लेखन विधा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में एक अभिनव पहल **'पाती अपनों को मुहिम'** का शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य के टोंक जिले के पीपलू उपखंड में 5 सितम्बर, 2018 को शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक द्वारा अपने शिष्य को पत्र लिखकर जीवन मूल्यों की सीख देने की भावना से इस मुहिम की नींव रखी गई।

विस्तार और उपलब्धियां

यह पहल धीरे-धीरे एक व्यापक जनआंदोलन का रूप लेती गई। इसके अंतर्गत अब तक 22 विषय आधारित पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनमें सवा तीन लाख से अधिक पत्र लिखे जा चुके हैं। साथ ही चयनित पत्रों के संकलन पर आधारित 16 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जा चुका है।

जनभागीदारी और प्रभाव

इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापक जनभागीदारी है। इसमें स्कूली विद्यार्थी, पेशेवर, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी और आमजन सभी सक्रिय रूप से सहभागी बन रहे हैं। आज यह मुहिम भारत के 23 से अधिक राज्यों तथा 10 देशों में रह रहे भारतीय परिवारों तक अपनी पहुंच बना चुकी है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

मुहिम का महत्व

'पाती अपनों को मुहिम' केवल संवादहीनता को कम करने का माध्यम

भर नहीं है, बल्कि यह समाज में संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करने का एक प्रभावी प्रयास बनकर उभरी है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी, खासकर स्कूली विद्यार्थियों में इस पहल ने सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही उनकी सृजनशीलता, अभिव्यक्ति क्षमता और लेखन कौशल में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, जो उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उद्देश्य

इस मुहिम के प्रमुख उद्देश्य हैं –

- पारस्परिक संवाद के माध्यम से रिश्तों में बढ़ती दूरियों को कम करना।
- युवा पीढ़ी में रचनात्मक सोच का विकास करना।
- सामाजिक समरसता एवं जीवन मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक एवं सजग बनाना।
- सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल करना।
- पत्रों के माध्यम से रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और आत्मीयता को पुनः स्थापित करना।

पत्र प्राप्ति का माध्यम

'पाती अपनों को मुहिम' पूर्णतः एक अनार्थिक एवं निष्पक्ष पहल है, जिसका उद्देश्य केवल मानवीय संवेदनाओं और संवाद को सशक्त बनाना है। इस मुहिम की विशिष्टता यह है कि प्रतियोगिता की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि सभी प्रतिभागियों को अपने पत्र हस्तलिखित रूप में कागज पर लिखने होंगे। साथ ही, इन पत्रों की प्राप्ति केवल डाक माध्यम के जरिए ही स्वीकार की जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल पत्र लेखन की पारंपरिक विधा को संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि लिखने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित होता है।

अब तक का सफर

'पाती अपनों को मुहिम' पहल में पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने हेतु मां की पाती बेटी को, पिता के पत्र संतान को, बेटी के पत्र बाबुल को, चिट्ठियां माई के नाम, बच्चों के पत्र अभिभावकों को तथा पत्र मीत को जैसे भावनात्मक विषय शामिल किए गए हैं। साथ ही प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 'प्रकृति की पाती मानव के नाम' और 'गौरैया की पाती' जैसे विषयों पर भी पत्र लिखवाए गए हैं। युवा पीढ़ी को सही दिशा और जीवन मूल्यों से जोड़ने के उद्देश्य से 'पाती युवाओं के नाम', 'बापू की चिट्ठी मेरी जुबानी' तथा 'अभिभावकों का पत्र शिक्षक को' जैसे विषय रखे गए, जबकि लोगों को उनकी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने के लिए 'माटी की पाती मेरे नाम' विषय को सम्मिलित किया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु बच्चों द्वारा मतदाताओं को संबोधित करते हुए 'बच्चों की पाती मतदाताओं के नाम' तथा देश के वीर सैनिकों के सम्मान में 'पाती वीर जवानों को' जैसे विषयों पर भी पत्र लेखन कराया गया है।

पुस्तक प्रकाशन

प्रतियोगिता के आयोजन के पश्चात प्राप्त पत्रों का विधिवत मूल्यांकन किया जाता है और उनमें से चयनित उत्कृष्ट पत्रों के संकलन के आधार पर पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल श्रेष्ठ रचनाओं को संरक्षित किया जाता है, बल्कि उन्हें व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने का भी अवसर प्राप्त होता है। अब तक इस मुहिम के अंतर्गत कुल 15 पुस्तकों का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया जा चुका है, जो इस पहल की निरंतरता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

भावनाएं साझा कर रहे बच्चे

'पाती अपनों को मुहिम' का प्रभाव समाज के विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां अब लोग एक-दूसरे को पत्र लिखने लगे हैं और विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थी इस विधा की ओर निरंतर उन्मुख हो रहे हैं। बच्चे अब किसी विशेष अवसर पर महंगे उपहारों के स्थान पर पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाएं और खुशियां साझा करने लगे हैं, जिससे संबंधों में आत्मीयता और गहराई बढ़ी है। विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं तथा छात्रावासों में पत्र विधा पर आधारित पुस्तकों से पत्रों का वाचन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों में सकारात्मक मूल्य विकसित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभिभावक और शिक्षक भी बच्चों को इस विधा से संबंधित पुस्तकें भेंट करने लगे हैं, जिससे इसे और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। इस पहल के परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में वृद्धि हुई है तथा उनमें रचनात्मकता के साथ-साथ चिंतनशीलता का भी विकास हुआ है। ■

पंच गौरव से निखर रही
जनजाति क्षेत्र की तैराकी प्रतिभाएं

उदयपुर में आदिवासी बच्चों ने सीखी तैराकी की बारीकियां

विनय सोमपुरा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देने की सोच अब जमीन पर प्रभावी रूप से साकार होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रारंभ किए गए "पंच गौरव" कार्यक्रम ने न केवल ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

राजस्थान विविधताओं का प्रदेश है। यह विविधता भौगोलिक होने के साथ ही सांस्कृतिक और प्राकृतिक भी है। इन विविधताओं के आधार पर ही प्रदेश के हर जिले की अपनी विशेषताएं हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हर जिले की इन्हीं विविधताओं को पंच गौरव में पिरोकर संरक्षित और संवर्धित करने की अनूठी पहल की। इसी क्रम में उदयपुर जिले में "एक जिला, एक खेल" अवधारणा के तहत तैराकी को विशेष खेल के रूप में विकसित करने का निर्णय इस क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप साबित हो रहा है। जल स्रोतों से समृद्ध इस क्षेत्र में अब तैराकी केवल पारंपरिक कौशल नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में उभर रही है।

खेलगांव में तैयार हो रहा ऑलवेदर स्विमिंग पूल

महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में तैराकी अभ्यास के लिए 50 मीटर स्विमिंग पूल बना हुआ है। राज्य सरकार की विशेष पहल पर पंच गौरव कार्यक्रम के तहत इस स्विमिंग पूल को तकरीबन साढ़े 6 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ऑलवेदर पूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

समर्पित प्रयासों से प्रतिभाओं की पहचान

राज्य सरकार के इस नवाचार को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन उदयपुर ने ब्लॉक स्तर पर आयोजित टैलेंट सर्च प्रतियोगिताओं के माध्यम से छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य किया। प्रत्येक ब्लॉक से 10-10 खिलाड़ियों का चयन कर कुल 170 प्रतिभाशाली तैराकों को महाराणा प्रताप खेलगांव में 15 दिवसीय निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर केवल अभ्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे एक समग्र विकास कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को तकनीकी दक्षता, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती तीनों पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया।

आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण

शिविर में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुभवी प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को ड्राइलैंड वर्कआउट, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल की आर्म एक्शन, किकिंग, ब्रीदिंग, फ्लोटिंग, लेग मूवमेंट, स्टार्ट तकनीकों, फिनिशिंग आदि का क्रमबद्ध अभ्यास करवाया। प्रशिक्षण की

विशेषता यह रही कि प्रत्येक खिलाड़ी की व्यक्तिगत कमियों का सूक्ष्म विश्लेषण कर उन्हें सुधारात्मक सुझाव दिए गए। इससे खिलाड़ियों की तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। शिविर के अंतर्गत सैद्धांतिक कक्षाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को तैराकी प्रतियोगिताओं की संरचना, नियमों और प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, खेलों में करियर की संभावनाओं, छात्रवृत्तियों और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

75 फीसदी जनजाति बच्चे, पहली बार देखा स्विमिंग पूल

आवासीय तैराकी शिविर में जिले भर से चुने गए कुल 170 नन्हें तैराकों में से 75 प्रतिशत जनजाति वर्ग से हैं। इनमें से अधिकांश बच्चों ने स्विमिंग पूल ही पहली बार देखा। तैराकी के लिए विशेष ड्रेस और गोगल्स आदि होते हैं, यह भी उन्हें शिविर में आकर पता चला। जब यह सभी वस्तुएं उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराकर निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

उदयपुर ने दिए हैं कई अंतरराष्ट्रीय तैराक

झीलों की नगरी उदयपुर में तैराकी सदियों से आमजन के लिए पसंदीदा मनोरंजन और खेल साधन रहा है। झीलों, तालाबों में तैराकी का अभ्यास किया जाता था। सन् 1967-68 में राजस्थान महिला विद्यालय में पहला तरणताल बना और राष्ट्रीय विद्यालयी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें अजमेर की तैराक सुश्री रीमा दत्ता व्यक्तिगत चैम्पियन रहीं और भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ तैराक घोषित कर उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1969 से 1973 तक उदयपुर में कई तैराकों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। वर्ष 1973 में श्री विक्रम सिंह चन्देल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया। उदयपुर की भक्ति शर्मा ने इंग्लिश चैनल पार किया। गौरवी सिंघवी, युग चैलानी, निखिल जांगिड़, विधि सनाढ्य, विद्यान सनाढ्य जैसे तैराकों ने उदयपुर को गौरवान्वित किया। पैरा स्विमिंग में जगदीश तेली, जमनालाल ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। ■

धींगा गवर

जोधपुर की गलियों में जीवंत होती नारी शक्ति, आस्था और लोकसंस्कृति की अनुपम गाथा

आकांक्षा पालावत, जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान की सांस्कृतिक धरा पर जोधपुर एक ऐसा नगर है, जहां इतिहास केवल स्मारकों में ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में भी झलकता है। किलों और महलों की भव्यता के साथ-साथ यह नगर अपनी लोकपरंपराओं, उत्सवों और अनूठी सामाजिक रीतियों के लिए विश्वविख्यात है। इन्हीं परंपराओं में एक अद्वितीय और जीवंत उत्सव है धींगा गवर मेला, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्त्री–शक्ति, सामाजिक समानता और लोक-आनंद का सशक्त उत्सव भी है।

साधना से उत्सव तक – सोलह दिनों की आस्था की यात्रा

चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलने वाला यह सोलह दिवसीय अनुष्ठान, अपने चरम पर उस रात्रि में पहुंचता है, जब होलिका दहन के सोलह दिन पश्चात जोधपुर का भीतरी परकोटा चांदनी, उल्लास और रंगों से सराबोर हो उठता है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि साधना और उत्सव का संगम है, जहां महिलाएं 'गवर माता', जिन्हें पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है, की आराधना कर अपने परिवार के मंगल और सौभाग्य की कामना करती हैं।

समावेशिता की मिसाल – हर स्वरूप में नारी का सम्मान

इस उत्सव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी समावेशी प्रकृति है। जहां प्राय: अनेक पारंपरिक आयोजनों में सामाजिक सीमाएं देखी जाती हैं, वहीं धींगा गवर में सुहागिनों के साथ-साथ विधवा महिलाएं भी समान श्रद्धा और अधिकार के साथ पूजन में सहभागी होती हैं। यह परंपरा नारी के हर स्वरूप को सम्मान देने और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने का एक जीवंत उदाहरण है।

बेंतमार परंपरा – लोकविश्वास और उल्लास का संगम

धींगा गवर मेले का सबसे आकर्षक और चर्चित आयाम है 'बेंतमार' परंपरा। आधी रात के पश्चात जब गलियां लोकगीतों और ढोल-नगाड़ों की थाप से गूंज उठती हैं, तब पारंपरिक वेशभूषा में सजी तीजणियां हाथों में बेंत लेकर सड़कों पर निकलती हैं। वे स्वांग रचते हुए कुंवारे युवकों को हल्के-फुल्के अंदाज में बेंत से स्पर्श करती हैं। लोकमान्यता है कि जिस युवक

को यह बेंत लगती है, उसके विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। यह परंपरा हंसी-ठिठोली के बीच सामाजिक संबंधों में सहजता और मधुरता का संचार करती है।

स्वांग में अभिव्यक्ति – स्त्री सृजन और स्वतंत्रता का मंच

धींगा गवर का महत्व केवल इन रोचक परंपराओं तक सीमित नहीं है। यह उत्सव स्त्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अद्वितीय मंच है। इस दिन महिलाएं समाज के विभिन्न रूपों का स्वांग रचती हैं-कोई श्रीकृष्ण बनती है, कोई महादेव, तो कोई पुलिस अधिकारी या लोकपात्र। यह केवल अभिनय नहीं, बल्कि उस सामाजिक संरचना का प्रतीकात्मक पुनर्पाठ है, जिसमें स्त्रियां अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और सामर्थ्य को निर्भीकता से अभिव्यक्त करती हैं। यह परंपरा स्पष्ट करती है कि लोकजीवन में स्त्री केवल मर्यादा की प्रतीक नहीं, बल्कि सृजन और शक्ति का भी केंद्र बिंदु है।

भव्यता और श्रद्धा – स्वर्णाभूषणों से सजी गवर माता

जोधपुर का यह मेला अपनी भव्यता के लिए भी विशिष्ट पहचान रखता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों सुनारों की घाटी, आड़ा बाजार, कुम्हारिया कुआं, खांडा फलसा और हटड़ियों का चौक में स्थापित गवर माता की प्रतिमाएं स्वर्ण आभूषणों और पारंपरिक श्रृंगार से सुसज्जित की जाती हैं। श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए स्वर्णाभूषणों से अलंकृत ये प्रतिमाएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि स्थानीय शिल्पकला और सामूहिक सहभागिता का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। प्रतिमाओं के श्रृंगार में लगने वाला समय, श्रम और समर्पण इस उत्सव की गरिमा को और भी ऊंचाई प्रदान करता है।

लोकगीतों में जीवित रिश्तों की मिठास

इस अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत भी इस परंपरा का अभिन्न अंग हैं। इन गीतों में पीहर, ससुराल, ननिहाल और समस्त परिवार की सुख-समृद्धि की कामना निहित होती है। इस प्रकार यह उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और सामाजिक ताने-बाने को सशक्त बनाने का माध्यम भी है।

परंपरा और प्रशासन – सुरक्षा के साथ सांस्कृतिक संरक्षण

आधुनिक समय में भी इस परंपरा की प्रासंगिकता अक्षुण्ण बनी हुई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए किए गए समुचित प्रबंध, जैसे प्रवेश नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था, इस बात का प्रमाण हैं कि परंपरा और प्रशासनिक सजगता का संतुलित समन्वय इस उत्सव को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में सहायक है।

धींगा गवर मेला कोई सामान्य उत्सव नहीं, बल्कि जोधपुर की आत्मा का जीवंत उत्सव है – जहां आस्था और उल्लास, परंपरा और आधुनिकता, तथा मर्यादा और स्वतंत्रता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मेला नारी शक्ति के उस सशक्त स्वरूप को उजागर करता है, जो सदियों से समाज को दिशा देता आया है-स्वतंत्र, सशक्त और सृजनशील। ■

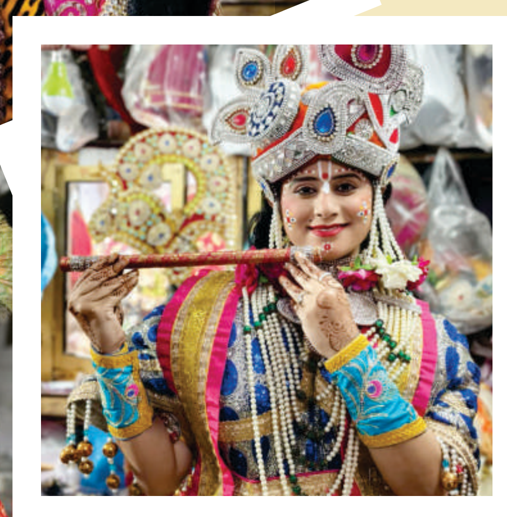

मन की सुनें जीवन चुनें

वंजुल सांखला, स्वतंत्र लेखिका

मानसिक स्वास्थ्य आज के समकालीन परिदृश्य में मात्र व्यक्तिगत सुख-शांति का विषय न रहकर सामाजिक संतुलन, उत्पादकता और समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक आधारभूत स्तंभ बन चुका है। तीव्र गति से परिवर्तित होती जीवनशैली, निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डिजिटल माध्यमों की सर्वव्यापकता तथा सामाजिक अपेक्षाओं के जटिल दबावों के बीच व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बनाए रखना एक गंभीर और बहुआयामी चुनौती के रूप में उभरा है। ऐसे परिवेश में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक नीतिगत और सामाजिक अनिवार्यता बन गया है। इस संदर्भ में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा किए गए समन्वित, दूरदर्शी और संवेदनशील प्रयास एक सुदृढ़, समावेशी एवं सुलभ मानसिक स्वास्थ्य तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल का संकेत देते हैं, जिनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, किफायती और प्रभावी सेवाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाकर एक संतुलित, जागरूक और मानसिक रूप से सशक्त समाज की आधारशिला रखना है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)

मानसिक विकारों के बढ़ते बोझ को प्रभावी रूप से कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, स्नातकोत्तर (पीजी) विभागों के सुदृढ़ीकरण तथा मानव संसाधन विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि प्रशिक्षित विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के माध्यम से मानसिक रोगों की समयबद्ध पहचान, प्रबंधन और उपचार को जिला स्तर तक सुलभ बनाया गया है। डीएमएचपी के अंतर्गत कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परामर्श सेवाएं, सामुदायिक जागरूकता अभियान, रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन जैसी बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। डीएमएचपी को 1 अप्रैल, 2026 से देश के 767 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।इसके अतिरिक्त, जिला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर दीर्घकालिक और निरंतर देखभाल सुनिश्चित कर इस कार्यक्रम को एक समग्र, सुलभ और जन-केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य ढांचे के रूप में विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

केंद्र सरकार द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को 'राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया गया। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53 'टेली मानस' सेल स्थापित किए जा चुके हैं और वहां टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। टेली मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। मार्च,2026 तक हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 34.34 लाख कॉल अटेंड की जा चुकी हैं। टेली-मानस सेवा का उद्देश्य देशभर में जरूरतमंद लोगों को 24×7 सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराना है। इसके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14416 या 1800-891-4416 के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कभी भी विशेषज्ञों से जुड़ सकता है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य है हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाना। साथ ही, एक ऐसा समग्र नेटवर्क विकसित करना जो परामर्श के साथ-साथ चिकित्सा और मनोसामाजिक सेवाएं भी प्रदान करे तथा विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों और कमजोर वर्गों तक इन सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं वास्तव में सर्वसुलभ बन सकें।

टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन

केंद्र सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर, 2024) के अवसर पर टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया। टेलीमानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जिसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विकसित किया

गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके), किशोर-हितैषी स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी), सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (एएच एंड डब्ल्यूडी) जैसी पहलों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जाती है तथा परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सहकर्मी प्रशिक्षक समुदाय में 15-20 लड़कों और लड़कियों के समूह बनाए जाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सहित किशोर स्वास्थ्य पर साप्ताहिक एक से दो घंटे के सहभागी सत्र आयोजित किए जाते हैं।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत राजस्थान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (आरएसएमएचए) का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीकरण करना तथा संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता की निगरानी करना है। यह प्राधिकरण राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित, जवाबदेह और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या की रोकथाम हेतु Raj-MAMTA (Rajasthan Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All) कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में काउंसलिंग और टेली-मेडिसिन सुविधाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ स्थापित किया जाएगा। साथ ही, जिला मुख्यालयों पर मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान, परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाओं हेतु मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे। जिला चिकित्सालयों में मनोरोग विशेषज्ञों के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलर्स की नियुक्ति की जाएगी, जबकि विद्यालयों और महाविद्यालयों में तनाव प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक काउंसलिंग एवं जागरूकता सत्र आयोजित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, कारागृहों में बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए काउंसलिंग एवं थैरेपी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं।

जागरूकता से उपचार तक

मानसिक रोगों के सामान्य लक्षणों में उदासी, चिंता, रुचि की कमी, व्यवहार में बदलाव, सामाजिक दूरी और नकारात्मक विचार शामिल हैं। इनसे बचाव के लिए नियमित दिनचर्या, योग-ध्यान, सकारात्मक सोच, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है। आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ से परामर्श, दवाओं का नियमित सेवन और परिवार का सहयोग उपचार में सहायक होता है। समय पर पहचान और सही देखभाल से अधिकांश मानसिक रोग नियंत्रित या ठीक हो सकते हैं, जिससे एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण संभव है। ■

मनदर्पण
MENTAL WELLBEING OF ADOLESCENTS

बेहद जरूरी है ...

स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना

अपने दोस्तों/क्लासमेट/रुम मेट के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना

मानसिक स्वस्थ रहने के आसान उपाय

- पर्याप्त नींद लें।
- दोस्त बनाये एवं परिवार से जुड़े रहें।
- संतुलित आहार लेवें एवं नशे से दूर रहें।
- अपनी भावनाओं को संतुलित रखें एवं दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।
- सकारात्मक पहलुओं, व्यक्तियों और अनुभवों को पहचानें एवं उनके लिए आभार व्यक्त करें।
- सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें।
- मन की भावनाओं को भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें।
- दैनिक जीवन में योग, प्रणायाम एवं ध्यान को अपनाएं।
- आवश्यकता होने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें।

Tele MANAS
National Tele Mental Health Programme
14416

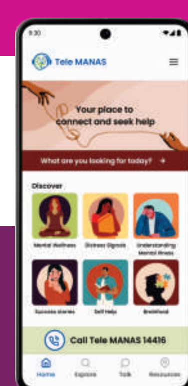

मानसिक स्वास्थ्य से
संबंधित परामर्श के लिए संपर्क करें

14416

1800-89-14416

प्रवेशोत्सव 2026 : शिक्षा से सशक्त भविष्य की ओर बढ़ता राजस्थान

सत्रारंभ के साथ शिक्षारंभ – सरकारी स्कूलों में बढ़ता विश्वास और बदलती तस्वीर

राजेश यादव, सहायक निदेशक

राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026–27 की शुरुआत इस बार केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सशक्त जन-आंदोलन के रूप में सामने आई है। 'प्रवेशोत्सव 2026' ने शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा, नई सोच और व्यापक जनभागीदारी का परिचय दिया है। 'सत्रारंभ के साथ शिक्षारंभ' का स्पष्ट और प्रभावशाली संदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में इस अभियान की आत्मा बनकर उभरा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा की शुरुआत पहले दिन से ही पूर्ण संकल्प और व्यवस्था के साथ हो।

घर-घर संपर्क – शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

इस वर्ष प्रवेशोत्सव का सबसे मजबूत पक्ष रहा – घर-घर संपर्क अभियान। शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया सघन अभियान केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का एक गंभीर प्रयास है। 4 चरणबद्ध तरीकों से चलाए जा रहे इस अभियान का पहला चरण 27 मार्च और दूसरा चरण 7 अप्रैल को समाप्त हुआ, जिसमें शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यालय स्टाफ और स्थानीय कार्मिकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस अभियान में 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण कर उनका नामांकन सुनिश्चित करने की यह पहल वास्तव में 'कोई बच्चा पीछे न छूटे' की भावना को साकार करती है।

नामांकन वृद्धि और ड्रॉपआउट में कमी की प्रभावी पहल

यह प्रयास न केवल नामांकन वृद्धि में महत्वपूर्ण रहा, बल्कि ड्रॉपआउट दर को कम करने की दिशा में भी एक निर्णायक पहल सिद्ध हुआ। 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष अभियान संचालित कर प्रत्येक घर तक पहुंच सुनिश्चित की गई, जिससे हर वंचित बालक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प साकार साकार किया जा सके।

सवेरे–सवेरे, यारों से मिलने, बन–ठन के निकले हम
सवेरे–सवेरे, यारों से मिलने, घर से दूर चले हम
रोके से ना रुकें हम, मर्जी से चलें हम
बादल–सा गरजें हम, सावन–सा बरसें हम
सूरज–सा चमकें हम - स्कूल चले हम

पहले दिन से पढ़ाई – संकल्प से सिद्धि तक

शिक्षा विभाग ने इस वर्ष एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सत्र के पहले ही दिन से शिक्षण कार्य पूरी तरह शुरू हो। 1 अप्रैल तक सभी जिलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर 'पहले दिन से पढ़ाई' के संकल्प को जमीन पर उतारा गया। यह पहल विद्यार्थियों में अनुशासन, निरंतरता और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म अनुदान – समानता की ओर मजबूत कदम

राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी 600 रुपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। इससे न केवल शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिला, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। यह पहल स्पष्ट करती है कि सरकार शिक्षा को केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा से जुड़ा विषय मानती है।

सुदृढ़ होती व्यवस्थाएं – बढ़ता विश्वास

विगत कुछ वर्षों में राजकीय विद्यालयों में हुए व्यापक सुधार अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन, स्मार्ट कक्षाएं, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, व्यावसायिक शिक्षा, खेल सुविधाएं और गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति ने सरकारी विद्यालयों की छवि को पूरी तरह परिवर्तित किया है। प्रशिक्षित शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज राजकीय विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि अवसरों के द्वार बन चुके हैं।

नई सोच, नया आत्मविश्वास

'प्रवेशोत्सव 2026' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो शिक्षा को हर घर, हर परिवार और हर बच्चे तक पहुंचाने का संकल्प लिए हुए है। यह पहल दर्शाती है कि जब सरकार, समाज और शिक्षा तंत्र मिलकर काम करते हैं, तो परिवर्तन केवल संभव नहीं, बल्कि निश्चित होता है।राजस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय कर रहा है, जहां हर बच्चा शिक्षित हो, सशक्त हो और अपने सपनों को साकार करने के लिए सक्षम हो। 'प्रवेशोत्सव 2026' इसी उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है - जहां शिक्षा केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन बन चुकी है।■

राज उन्नति : प्रदेश की प्रगति की परिवर्तनकारी पहल

हेमेन्द्र सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान ने एक बार फिर प्रशासनिक नवाचार के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभाते हुए राज उन्नति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह पहल न केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'प्रगति' (PRAGATI) मॉडल को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का सशक्त उदाहरण है, बल्कि ई-गवर्नेंस और सुशासन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की पहुंच (अन्त्योदय) सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरगामी और परिवर्तनकारी कदम भी है।

तकनीक से सुशासन की नई दिशा

"राज उन्नति" एक समन्वित डिजिटल मंच है, जिसमें डेटा प्रबंधन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एकीकृत कर प्रभावी शासन व्यवस्था विकसित की गई है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत पोर्टल पर राज्य की प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं को मैप किया गया है, जिससे उनकी निरंतर निगरानी और प्राथमिकता निर्धारण सुनिश्चित हो पाता है। संबंधित विभाग समयबद्ध रूप से अद्यतन जानकारी अपलोड करते हैं, जिसके आधार पर नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन होता है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को भी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है।

परिणाम आधारित कार्य संस्कृति की स्थापना

राज उन्नति सक्रिय नेतृत्व एवं और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति की सशक्त पहचान बन रहा है। राज उन्नति के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की नियमित मासिक समीक्षा कर रहे हैं।इन बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों और जिला प्रशासन के साथ सीधा संवाद स्थापित कर परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं के त्वरित समाधान एवं कार्य पूरा करने की समय सीमा का भी निर्धारण किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में अब तक राज उन्नति की तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके समयबद्ध क्रियान्वयन का निर्धारण किया गया।

आर्थिक और सामाजिक विकास का समन्वय

इस पहल के माध्यम से सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी आधारभूत संरचनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। साथ ही, युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि इस नवाचार के सामाजिक क्षेत्र में भी व्यापक दायरे को दर्शाती है।

जन-केंद्रित शासन का मज़बूत सेतु

प्रशासनिक व सामाजिक घटक के साथ ही राज उन्नति का एक महत्वपूर्ण आयाम जन-केंद्रित दृष्टिकोण भी है। राज उन्नति की बैठकों में राज संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परिवादियों से संवाद कर समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करते एवं उनसे फीडबैक भी लेते हैं। इसके अतिरिक्त बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में प्रशासनिक सचिवों द्वारा प्रतिदिन 10 परिवेदनाओं की समीक्षा हेतु विशेष मॉड्यूल संचालित किया जा रहा है। सचिव स्तर के अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेल्पलाइन केंद्रों का दौरा कर नागरिकों से सीधे संवाद करते हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि परिवेदनाओं का संतुष्टि स्तर फरवरी, 2026 के 69 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सराहना

केंद्र सरकार के 'प्रगति' मॉडल की तर्ज पर विकसित "राज उन्नति" को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त हो रही है। सक्रिय नेतृत्व, रणनीतिक योजना, समयबद्ध समीक्षा और सशक्त डिजिटल ढांचे के माध्यम से यह पहल एक ओर प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व प्रभावशीलता सुनिश्चित कर रही है, वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं में समयबद्ध प्रगति व जनकल्याणकारी योजनाओं में त्वरित गति लाने की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रधार बन रही है। ■

From Darkness to Development Dhaulapani GSS Transforms Rural Life

***Navdha Pardeshi**, APRO*

In the direction of realizing Prime Minister Shri Narendra Modi's resolve for a "Viksit Bharat" and under the leadership of Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma, the State Government is working with commitment to provide electricity, water, roads and other basic amenities to every village. As a result of this commitment, long-standing demands in remote areas of tribal-dominated districts like Pratapgarh are now being addressed on the ground. The establishment of the Dhaulapani Grid Sub-Station (GSS) in the Chhoti Sadri Panchayat Samiti area is a significant step in this direction, fulfilling a demand that had been consistently raised by local residents from long time.

From Power Cuts to Progress – A New Era Begins

For many years, ensuring quality power supply in the remote and tribal-dominated villages of Chhoti Sadri Panchayat Samiti remained a major challenge. Due to the long feeder length and persistent low-voltage issues, consumers frequently faced tripping problems. This directly affected irrigation activities, routine household work and children's education. Although electricity connections existed, irregular and unstable supply continued to trouble residents. In such circumstances, the demand for the Dhaulapani GSS kept gaining momentum over the past decade and a half. For local representatives and villagers alike, this was not merely a demand for convenience, but a basic necessity for smoother daily life. With the sustained efforts of the State Government, this long-awaited project has now been successfully realized.

Dhaulapani Power Feeder Established under the RDSS Scheme

Under the State Government's flagship Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS), the 33/11 KV Dhaulapani power feeder has been established. With a capacity of approximately 3.15 MVA, the project includes the construction of five new 11 KV feeders—Mandai, Manpura, Bhatkheda, Hasanpur ki Rail, and Dhaulapani-AG. Completed at an estimated cost of Rs. 2.32 crore , the project has directly benefited 2,419 consumers across several villages, including Chiveli, Tanda Ghata, Nanakwedi, Manpura, Chariyala Amba, Richwa, Bhatkheda, Hasanpur ki Rail, Patiya, Dhaulapani, Ghati Ghosi, and nearby settlements.

Better Power, Better Living for Rural Communities

Following the completion of the project, there has been a noticeable improvement in the quality of power supply across the region. Earlier, residents had to cope with frequent interruptions and low voltage, but now household appliances can be operated safely and power supply for agricultural activities has become more reliable. This has enhanced the efficiency of farmers and made it easier for rural households to meet their day-to-day needs.

Infrastructure Development Fueling Progress in Tribal Areas

Under the leadership of Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma, the State Government continues to work with dedication to ensure the availability of water, electricity, roads and other essential infrastructure in every village. In tribal-dominated regions such as Pratapgarh, projects of this nature play a vital role in accelerating development and creating new opportunities for social and economic progress. The Government's objective is to ensure that the benefits of development reach every section of society, in line with Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of a "Viksit Bharat" Ensuring the availability of drinking water and electricity in every household and connecting every region with strong infrastructure, remains central to this approach.

Beyond Infrastructure, A Symbol of Fulfilled Aspirations

The establishment of the Dhaulapani GSS is not merely an infrastructure project, it symbolizes the fulfillment of long-standing expectations of thousands of families in the region. It stands as an example of how effective implementation of development schemes can bring lasting solutions to remote areas and help overcome challenges that communities have faced for years. ■

प्रदेश नीति : विकास और गति

राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2026

बदलते समय की आवश्यकता...

शैलेन्द्र सिंह, राज.आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा

आज का युग केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। ऐसे समय में एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की शक्ति और आत्मनिर्भरता का आधार बन जाता है। भारत का एयरोस्पेस और रक्षा बाजार वर्तमान में तीव्र गति से विकास कर रहा है। इसके वर्ष 2026 तक 12.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत ने "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" जैसे अभियानों के माध्यम से इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने 12 मार्च 2026 को राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति, 2026 लागू की है, जो राज्य को इस रणनीतिक क्षेत्र में एक नए मुकाम पर ले जाने का प्रयास है।

नीति का उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य रक्षा उत्पादन और एयरोस्पेस क्षेत्र में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) तैयार करना है, जो राजस्थान को वैश्विक एयरोस्पेस एवं रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बना सके। इनके अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, वैश्विक निवेश आकर्षित करना, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना प्रमुख लक्ष्य हैं। साथ ही, एआई, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैटेरियल्स जैसे अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए उच्च कौशल आधारित रोजगार सृजन करना है।

राजस्थान की रणनीतिक विशेषताएं

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, विशाल भूमि संसाधन और मजबूत औद्योगिक आधार इसे इस क्षेत्र के लिए विशेष बनाते हैं। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ाव, विकसित सड़क और रेल नेटवर्क तथा एयर कनेक्टिविटी निवेशकों को आकर्षित करती है। राज्य में रक्षा प्रतिष्ठानों की उपस्थिति जैसे जोधपुर में डीआरडीओ लैब और जयपुर में दक्षिण-पश्चिमी कमान (मुख्यालय-जयपुर), महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (एमएफएफआर) इसे रक्षा गतिविधियों के लिए और अधिक उपयुक्त बनाती है । यहां उपलब्ध कुशल मानव संसाधन, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान इस नीति के लिए मजबूत नींव प्रदान करते हैं।

विनिर्माण और सेवा – दोनों का महत्व

नीति में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में एयरक्राफ्ट, ड्रोन, रक्षा उपकरण, सैटेलाइट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च तकनीकी उत्पाद शामिल हैं। वहीं सेवा क्षेत्र में एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल), परीक्षण, सिमुलेशन, साइबर सुरक्षा और डिजाइन सेवाएं प्रमुख हैं। यह नीति केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण वैल्यू चेन को विकसित करने का प्रयास करती है।

विनिर्माण क्षेत्र

1. विमान, हेलीकॉप्टर एवं यूएवी निर्माण – डिजाइन, असेंबली एवं परीक्षण
2. एवियोनिक्स एवं एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स – नेविगेशन, रडार, संचार प्रणाली
3. अंतरिक्ष प्रणाली एवं उप-प्रणालियां – सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल कंपोनेंट
4. सैटेलाइट एप्लिकेशन एवं पेलोड – रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, रक्षा उपयोग
5. रक्षा विनिर्माण – हथियार, गोला-बारूद, मिसाइल, आर्म्ड वाहन
6. प्रिसिजन इंजीनियरिंग एवं कंपोनेंट्स – सीएनसी मशीन द्वारा निर्मित पार्ट्स, फास्टनर्स इत्यादि
7. प्रोपल्शन सिस्टम – जेट इंजन, रॉकेट इंजन, फ्यूल सिस्टम
8. टूलिंग, फिक्स्चर एवं ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट – जिग्स, फिक्स्चर, ट्रॉलियां, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट
9. स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एम्बेडेड सिस्टम – माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स
10. रोबोटिक्स एवं ऑटोनोमस सिस्टम – ड्रोन, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म

सेवा क्षेत्र

1. एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल) – विमान एवं यूएवी की मरम्मत सेवाएं
2. प्रशिक्षण एवं सिमुलेशन सेवाएं – पायलट प्रशिक्षण, फ्लाइट सिमुलेटर
3. डिजाइन, परीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएं – एयरोस्ट्रक्चर डिजायन, प्रोटोटाइप टेस्टिंग एवं डीजीसीए/सीईएमआईएलएसी प्रमाणन
4. एयरोस्पेस आर एण्ड डी एवं इंजीनियरिंग सेवाएं – अनुसंधान एवं नवाचार
5. लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन सेवाएं – वेयरहाउसिंग एवं सुरक्षित परिवहन
6. रक्षा, आई.टी. एवं साइबर सुरक्षा – डेटा सुरक्षा एवं सिस्टम इंटीग्रेशन
7. परीक्षण, कैलिब्रेशन एवं गुणवत्ता आश्वासन – NABL/ISO प्रमाणन
8. कंसल्टेंसी एवं अनुपालन सेवाएं – ISO, सैन्य आदि
9. आफ्टरमार्केट सपोर्ट एवं लाइफसाइकिल मैनेजमेंट - परिसंपत्ति ट्रैकिंग, पुर्जों का नवीनीकरण, अपग्रेड और प्रदर्शन-आधारित लॉजिस्टिक्स
10. स्पेस ऑपरेशन एवं सैटेलाइट सेवाएं – ग्राउंड स्टेशन, डेटा प्रोसेसिंग

प्रोत्साहन संरचना

एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयों के लिए यह सीमा 25 करोड़ रुपये रखी गई है और 25 से 50 करोड़ रुपये के निवेश को लार्ज श्रेणी में माना जाएगा। पहले से स्थापित लार्ज, मेगा या अल्ट्रा-मेगा इकाइयों द्वारा विस्तार निवेश भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र होगा। वहीं सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए मानक प्रोत्साहन पैकेज का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 25 करोड़ रुपये का पात्र स्थायी पूंजी निवेश आवश्यक है।

राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की है। उद्योगों को तीन प्रमुख विकल्प दिए गए हैं–निवेश सब्सिडी, पूंजी सब्सिडी और टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन, प्राथमिकता क्षेत्रों में निवेश और एंकर यूनिट्स के लिए अतिरिक्त बूस्टर भी प्रदान किए जाते हैं। बिजली शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि लागत में छूट से उद्योगों का प्रारंभिक खर्च काफी कम हो जाता है, जिससे निवेश का माहौल और अनुकूल बनता है।

प्रशासनिक अवसंरचना

- नोडल विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- सहायक एजेंसी : रीको
- आवेदन पोर्टल : राजनिवेश

निवेश हेतु समितियां

- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति : 25 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के लिए, अध्यक्ष – उद्योग विभाग के सचिव।
- जिला स्तरीय स्वीकृति समिति : 25 करोड़ रुपये से कम एवं एमएसएमई के लिए, अध्यक्ष – जिला कलेक्टर।
- स्टेट एम्पावर्ड कमेटी : कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए, अध्यक्ष – मुख्य सचिव।

एमएसएमई, स्टार्टअप और कौशल विकास : समावेशी विकास की दिशा

यह नीति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देती है। उन्हें वित्तीय सहयोग, इन्क्यूबेशन सुविधाएं और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ताकि वे भी रक्षा उत्पादन की मुख्यधारा से जुड़ सकें। साथ ही, इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और उद्योग–शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने हैं। इस प्रकार यह नीति समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत बनाने का माध्यम है।

सतत विकास और नवाचार

नीति में हरित विकास और नवाचार को भी महत्व दिया गया है। पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, गुणवत्ता मानकों, पेटेंट और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित कर राजस्थान को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है।

राजस्थान एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति, 2026 केवल एक औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की एक स्पष्ट दिशा है। यह नीति राजस्थान को एक उच्च तकनीकी, नवाचार आधारित और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का मजबूत आधार प्रदान करती है। "राइजिंग राजस्थान" के विज़न को साकार करते हुए यह नीति "विकसित राजस्थान" की ओर एक निर्णायक कदम है, जहां उद्योग, नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ते हैं। यह नीति न केवल निवेश और रोजगार बढ़ाएगी, बल्कि राजस्थान को भारत के रणनीतिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र भी बनाएगी। ■

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति–2026

आत्मनिर्भर राजस्थान की ओर ठोस कदम

अम्बिका शर्मा, स्वतंत्र लेखिका

किसी भी प्रदेश की उन्नति उसके युवाओं के सम्पूर्ण विकास पर निर्भर करती है। इसमें प्रदेश सरकार कितनी सफल है इसका पैमाना रोज़गार के अवसर पैदा करने के साथ घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने से लगाया जा सकता है। राजस्थान सरकार भी इस कसौटी पर सफल होने के लिए विश्व–स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने पर कार्य कर रही है, ताकि राजस्थान को भविष्य के औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। यह पहल 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहां औद्योगिक विस्तार के लिए विशाल भूमि उपलब्ध होना भी एक बड़ा कारण है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति–2026 राजस्थान सरकार द्वारा लागू की होने वाली महत्वपूर्ण नीति मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना, निवेश को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लाई गई यह नीति एक बेहतर औद्योगिक ईको-सिस्टम तैयार करने पर केंद्रित है, जिससे राजस्थान को एक आधुनिक और भरोसेमंद औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

एक मजबूत औद्योगिक ईको–सिस्टम की दिशा में कदम

इस नीति का मूल उद्देश्य केवल औद्योगिक पार्कों की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यापक ईको-सिस्टम तैयार करना है जहां उद्योगों को जमीन, संसाधन, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर सुगमता से मिल सकें। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'राइजिंग, रिलायबल एंड रिसेप्टिव' भारत के विजन के अनुरूप है और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को भी मजबूती प्रदान करती है। इससे बड़े निवेशकों के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी समान रूप से लाभ मिलेगा।

विकास के चार मॉडल

नीति की एक प्रमुख विशेषता औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए चार अलग-अलग मॉडल का प्रावधान है, जो निवेशकों को उनकी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकल्प प्रदान करता है। इनमें सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराना, निजी डेवलपर्स द्वारा विकास करना या दोनों के संयुक्त प्रयास शामिल हैं। इस लचीले ढांचे से अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित होती है और विकास प्रक्रिया को गति मिलती है। साथ ही, न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की अनिवार्यता से यह सुनिश्चित किया गया है कि औद्योगिक पार्क सुव्यवस्थित और प्रभावी हों।

राजस्थान में भजनलाल सरकार हर वर्ग के विकास के लिए मजबूती से प्रयास कर रही है। विशेष रूप से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति से बड़े निवेशकों के साथ छोटे उद्योगपतियों को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी।

सौरभ खण्डेलवाल
निदेशक, डीजीएस ट्रांसलोजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

औद्योगिक विकास को मिली नई गति

बेहतर ईको-सिस्टम से होगी निवेश और रोजगार में वृद्धि

विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का होगा विकास

निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को चार विकास मॉडलों पर किया जाएगा विकसित

निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी अनिवार्य

- **कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क छूट**
- **स्टाम्प शुल्क एवं कन्वर्जन शुल्क में 25 प्रतिशत छूट**
- **प्लग-एंड-प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स-2024 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन**

उद्योग और पर्यावरण का संतुलन

इस नीति में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व दिया गया है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) के लिए सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, प्रारंभिक औद्योगिक पार्कों को पूंजीगत अनुदान देकर हरित और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार विकास के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी गंभीरता से निभा रही है।

मजबूत आधारभूत संरचना विकास की रीढ़

औद्योगिक विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा अत्यंत आवश्यक होता है और इस नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। औद्योगिक पार्कों तक जल, विद्युत और सड़क जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सड़क और संपर्क मार्गों के निर्माण में सरकार की भागीदारी से डेवलपर्स पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी और उद्योगों को सुचारू रूप से संचालन में सहायता मिलेगी।

पारदर्शिता और सरल प्रक्रियाएं

नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। "राज निवेश पोर्टल" के माध्यम से भूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए सभी आवश्यक अनुमतियां समयबद्ध तरीके से प्रदान की जाएंगी। इससे निवेश प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी, जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निवेश को मिलेगा बढ़ावा

इस नीति में निवेशकों को कई प्रकार के वित्तीय और नीतिगत लाभ प्रदान किए गए हैं, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क और कन्वर्जन शुल्क में रियायत तथा प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसे प्रावधान उद्योगों की स्थापना को आसान और किफायती बनाते हैं। इससे उद्योग तेजी से स्थापित हो सकेंगे और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। ऐसे में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति–2026 राजस्थान के औद्योगिक भविष्य की एक मजबूत आधारशिला बन सकती है। यह नीति निवेश, रोजगार और संतुलित विकास के बीच एक प्रभावी संतुलन स्थापित करती है। हरित विकास, आधुनिक अवसंरचना और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से यह पहल राजस्थान को एक ऐसे औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है, जो वर्तमान के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम है। ■

> **प्रदेश सरकार की औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 उद्योगों को विश्वस्तरीय विकसित करने के लिए सराहनीय पहल है। यह नीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे प्रदेश में निवेश को मजबूती के साथ उद्योगों के लिए एक सशक्त ईको सिस्टम तैयार होगा। यही नहीं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।**
>
> **अरुण गुप्ता**
> निदेशक- जुपिटर स्टैंपिंग जयपुर

शौर्य और रणनीति से ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले सेनानायक

लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़

चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नामकरण अब सगत सिंह राठौड़ के नाम पर

मनीष कुमार, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

राजस्थान, विशेषकर चूरू और शेखावाटी क्षेत्र, अपनी वीरता और बलिदान की गौरवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जहां पीढ़ियों से वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा करते आए हैं। इन्हीं में से एक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ हैं, जिन्हें उनके अटूट साहस, युद्ध कौशल और अद्वितीय सैन्य नेतृत्व के लिए गर्व से याद किया जाता है। वे गोवा मुक्ति संग्राम, 1971 के भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और नाथुला पास की लड़ाई के नायक रहे तथा पद्मभूषण से सम्मानित होकर भारतीय सेना के प्रेरणास्रोत बने।

चूरू में जन्मे वीर ने भारत-पाक युद्ध में किया नेतृत्व

चूरू के वीर सेनानायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ ने भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण नेतृत्व करते हुए भारतीय सेना की शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका जन्म 14 जुलाई, 1919 को कुसुमदेसर गांव में हुआ। 1938 में उन्होंने डूंगर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया और महाराजा गंगा सिंह की बीकानेर स्टेट फोर्स (गंगा रिसाला) में नायक पद से सैन्य जीवन शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अधिकारी के रूप में कमीशन मिला और उन्होंने मिस्र, सीरिया तथा फिलिस्तीन में सेवाएं दीं। अपने सैन्य करियर में उन्होंने तीन देशों के साथ युद्धों में भाग लिया और सभी में विजय प्राप्त की। वे ऐसे पहले सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने युद्ध के बाद स्टाफ कॉलेज क्वेटा सहित दो प्रतिष्ठित स्टाफ कोर्स पूरे किए।

गोवा बना भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग

15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली शासन था, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय (1961) के तहत मात्र तीन दिन में समाप्त कर दिया गया। 17–19 दिसंबर 1961 के बीच भारतीय सेना ने गोवा पर कब्जा किया और वे पणजी में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने, जिन पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री सालाजार ने इनाम भी घोषित किया था। बाद में मेजर जनरल के रूप में उन्होंने 1967 में नाथुला पास पर चीन के खिलाफ निर्णायक विजय हासिल कर उसका भ्रम तोड़ा तथा मिजोरम में उग्रवाद को भी सफलतापूर्वक समाप्त किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1970 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उनके इस युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता पर 'पलटन' नाम से एक फिल्म भी बनी है।

लेफ्टिनेंट जनरल सगतसिंह और 1971 का भारत-पाक युद्ध

सगत सिंह ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। 4 कोर के नेतृत्व में उन्होंने तेज और रणनीतिक हमलों से मात्र 14 दिनों में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया। उन्होंने ढाका पहुंचने के लिए मेघना नदी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पार करने का साहसिक निर्णय लिया, जिसमें 110 उड़ानों द्वारा सैनिकों को नदी पर उतारा गया। यह "हेलिबॉर्न ऑपरेशन" का एक प्रभावी और नवीन प्रयोग था। कठिन भू-भाग (नदियों और नालों से भरे क्षेत्र) के बावजूद लगातार आक्रमण कर उन्होंने दुश्मन को कमजोर किया। अंततः पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए. ए. के. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ।

वीरता का किस्सा

उनकी वीरता के किस्सों में बताते हैं कि एक बार बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान वे हेलीकॉप्टर से लड़ाई का जायजा लेने गए व युद्ध स्थल पर ही लैंड कर गए तो मुआयने के दौरान ही उनके हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों से पायलट बुरी तरह जख्मी होने से सह पायलट ने नियंत्रण संभाला और हेलीकॉप्टर वापस अगरतला आया। हेलीकॉप्टर में गोलियों से 64 सुराख हो गए, लेकिन जनरल सगत सिंह पर इसका कोई असर न हुआ और वे एक दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर निरीक्षण पर निकल पड़े।

तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हुए सम्मानित

लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को उनके उत्कृष्ट सैन्य योगदान, विशेषकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भूमिका के लिए पद्म भूषण (तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश सरकार ने भी उन्हें मरणोपरांत "मुक्ति संग्राम के मित्र" सम्मान दिया। उन्होंने दिसंबर 1974 में सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में निवास किया और 26 सितंबर 2001 को उनका निधन हो गया। मार्च 2013 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने उनके परिवार को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सराहा।

चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम अब लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 8 मार्च, 2026 को चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित गौरव सेनानी समारोह में चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नाम 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर किए जाने की घोषणा की है। ■

महिलाएं अपने सपनों को पंख दें राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 10 अप्रैल को
'नारी शक्ति वंदन'
कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद किया

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा ...

सनातन संस्कृति में महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है। ये आधी आबादी घर को संभालने के साथ ही देश-प्रदेश के विकास में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में करीब 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर दिया जा रहा ध्यान

राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है। 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 5 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार ने इस योजना की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 11 लाख 58 हजार गर्भवती महिलाओं को 576 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। ''मा वाउचर योजना' से गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा भी मिल रही है। इसके अतिरिक्त 'पीएम पोषण योजना', 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान', 'मिशन इंद्रधनुष' और 'सक्षम आंगनबाड़ी योजनाएं' संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अजमेर से एचपीवी वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। यह पहल प्रदेश की युवतियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ■

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सम्बोधन से...

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों का पूरा ध्यान रखती हैं और वे इस भावी पीढ़ी की नींव को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। पिछले दो वर्ष में आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक कम हेल्पर सहित समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी। अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध दिया जा रहा है तथा आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण-मरम्मत का कार्य भी करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्ट फोन दिए गए हैं।साथ ही, आगामी समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आंखों की निःशुल्क जांच कर उन्हें चश्मा भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की नींव को कर रहीं मजबूत

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफार्म के लिए 1-1 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। इस दौरान श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चैक सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से ही सशक्त-आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है। इसी को ध्येय मानते हुए राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित

श्री शर्मा ने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही देश-प्रदेश का विकास संभव है। राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। साथ ही, इस वर्ष के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मा वाउचर योजना सहित विभिन्न योजनाओं द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। ■

पिछड़े, वंचित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच रहा विकास का उजियारा

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेंशन एवं पालनहार योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 1 हजार 363 करोड़ रुपये का राशि हस्तांतरित की। उन्होंने 10 छात्रावास भवनों का लोकार्पण, 17 भवनों का शिलान्यास करने के साथ ही जामडोली स्थित स्वयंसिद्धा परिसर में लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही, एआई आधारित 'हेल्प डेस्क समाधान साथी' का शुभारंभ भी किया। उन्होंने विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण एवं कन्यादान योजना के लाभार्थियों को राशि का वितरण किया। समारोह में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी स्थापित करने एवं अंबेडकर पीठ, मूंडला, जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केन्द्र की स्थापना की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा पर आधारित दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही, विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरणों का भी वितरण किया।

बाबा साहेब के सपने हो रहे साकार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़े, वंचित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाने एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलते हुए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार बाबा साहेब के सपनों को पूरा करते हुए समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त एवं सक्षम करने का कार्य कर रही है।

पिछड़े एवं वंचित वर्ग का हो रहा सर्वांगीण विकास

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार के प्रकरणों में 28 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। वहीं, शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 292 करोड़ रुपये व्यय कर 3 लाख 75 हजार विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 534 करोड़ रुपये खर्च कर 3 लाख 21 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1 लाख 62 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में ढाई हजार से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

अंत्योदय की भावना के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन बना मिसाल

राज्य सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में मिसाल कायम की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में हमारा राज्य देश भर में अग्रणी हैं। पीएम-जनमन योजना के तहत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में हम पूरे देश में अव्वल हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार में पारदर्शिता के कारण सभी भर्ती परीक्षाएं समय से आयोजित हो रही हैं और इससे बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के युवाओं को लाभ भी मिल रहा है। ■

राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट का निरीक्षण

परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को मिलेगा पर्याप्त जल- मुख्यमंत्री

बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील स्थित गुहाटा गांव में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा को परियोजना की प्रगति की पूरी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि चम्बल एक्वाडक्ट कोटा के पीपल्दा समेल गांव तथा बूंदी के गुहाटा गांव के मध्य चम्बल नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 2 हजार 280 मीटर है। एक्वाडक्ट का निर्माण 5060 पाइलों एवं 77 पाइल कैपों पर किया जाएगा। एक्वाडक्ट में औसतन 384 गोलाकार पीयरों का निर्माण होगा।

साथ ही, इसके जरिए चम्बल नदी के ऊपर जल का प्रवाह किया जाकर चम्बल नदी को क्रॉस किया जाएगा जिससे आमजन के लिए आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने एक्वाडक्ट पीयर का पूजन किया। उन्होंने प्रोजेक्ट साइट पर राम जल सेतु लिंक परियोजना के निर्माण कार्यों को लेकर तैयार की गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले श्री शर्मा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा तथा प्रदेश की लगभग 40 फीसदी आबादी इससे लाभान्वित होगी। चम्बल एक्वाडक्ट राम जल सेतु लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। ■

कृषि के विकास का रोडमैप बना रही राज्य सरकार

करौली जिले में टोडाभीम के नांगल शेरपुर गांव में 8 अप्रैल को किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दो महत्वपूर्ण मार्गों करीरी-गाजीपुर-भैरोजी से राजौर वाया मेरेडा-खेडी, जैचडी-माचडी और पथवारी से घासीराम बाबा आश्रम कदम खुण्डी वाया मातासूला-पाडली खुर्द सड़क निर्माण करने एवं नांगल शेरपुर तहसील बालघाट में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की।

आधुनिक कृषि तकनीक अपनाएं किसान

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध करवाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना व यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके साथ ही, आईएनजीपी, गंगनहर और सोम-कमला-अम्बा सहित अनेक परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में कृषि के विकास का रोडमैप भी बना रही है।

पशुओं के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित

श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा चुका है और गांवों में पशुओं के घर पर ही इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन सेवा दे रहे हैं। वहीं राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पशुपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है।

राज्य सरकार ने करौली के विकास को दी गति

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने करौली जिले के विकास के लिए 2 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की बजट घोषणाएं की है। 60 करोड़ रुपये की लागत से सलेमपुर से बालोती-डाबरा-शेखपुरा-गोठरा-बरवासन देवी-नरौली सड़क मय हाईलेवल ब्रिज का काम प्रारम्भ हो चुका है। 25 करोड़ रुपये की लागत से नादोती-श्रीमहावीरजी खेड़ा रोड, गम्भीर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 22 करोड़ रुपये की लागत से मोठियापुरा से जगर वाया हरिरामपुरा सड़क मार्ग के विकास सहित कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। ■

किसान हैं इस देश की आत्मा

पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन

जयपुर में पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारत की रीढ़ है तथा किसान इस देश की आत्मा हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि देश की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पहले क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान से किया गया है। सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा तथा राजस्थान राज्य शामिल हैं तथा इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का एक मंच मिलेगा। साथ ही, सम्मेलन से राज्यों के बीच आपसी समन्वय व नवाचारों को भी साझा कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

कृषि बजट में की ऐतिहासिक वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने विकसित राजस्थान@2047 की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण किया है। राज्य सरकार ने कृषि बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान आज बाजरा, सरसों और ईसबगोल जैसे उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर है, जिसे अब प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। साथ ही, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान कृषि में नई ऊंचाइयां छू रहा है। राज्य सरकार द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना समझौता, आईएनजीपी, गंगनहर और सोम-कमला-अम्बा सहित अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ■

कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

सुशासन के संकल्प को करें साकार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन सचिवालय राज्य प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, जहां से राज्य की सभी नीतियों एवं योजनाओं की शुरुआत कर आमजन को लाभान्वित किया जाता है। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो सरकारी कामकाज में तेजी आती है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाए।

ग्रेच्युटी सीमा अब 25 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सवा दो साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्नति दी जा रही है तथा ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही, आरजीएचएस के तहत महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्रवधू को शामिल, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 चरणों में स्वीकृति तथा महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनावमुक्त वातावरण देने के लिए 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' की स्थापना जैसे प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025 में सचिवालय के कार्मिकों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नवीन पदों का सृजन किया गया था। इसी क्रम में उन्होंने समयबद्ध पदोन्नति से और अधिक कार्मिकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 15 और पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जिन काडर में पदोन्नति के लिये पूर्व में छूट नहीं मिल पाई, उनके लिये 2 वर्ष की छूट की घोषणा की गई है। श्री शर्मा ने इस क्रम में मुख्य सचिव को सचिवालय सहित विभिन्न विभागों के सम्बंध में आवश्यकता निर्धारण कर शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिए। ■

सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. – 08

1. **निम्नलिखित में से कौनसे कार्यक्रम में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर है?**
   a) विकसित भारत संकल्प यात्रा b) पोषण माह 2025 गतिविधियों में
   c) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ) d) पीएम कुसुम योजना (कंपोनेंट A)
2. **राजस्थान की किस झील को पांचवें रामसर स्थल के रूप में नवीनतम जोड़ा गया है?**
   a) फतेहसागर b) पचपदरा c) सिलीसेढ़ d) सांभर
3. **निम्नलिखित में से HPV का सही पूर्ण रूप कौन-सा है?**
   a) ह्यूमन प्रोटीन वायरस b) हाई पावर वायरस
   c) ह्यूमन पैथोजन वैरिएंट d) ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
4. **'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' कब से कब तक संचालित किया जा रहा है?**
   a) 1 मार्च से 30 अप्रैल तक b) 10 मार्च से 20 मई तक
   c) 19 मार्च से 15 मई तक d) 25 मार्च से 31 मई तक
5. **राजस्थान के एकीकरण (विलय प्रक्रिया) को पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगे?**
   a) 2845 दिन b) 3144 दिन c) 3250 दिन d) 3000 दिन
6. **राज्य बजट 2026–27 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर कितनी राशि किए जाने की घोषणा की गई है?**
   a) 1 हजार 450 रुपये b) 1 हजार 675 रुपये
   c) 2 हजार रुपये d) 1 हजार 540 रुपये
7. **भारतीय संविधान में शामिल चित्रकलाओं को बनाने में निम्न में से किस चित्रकार का योगदान नहीं है?**
   a) नंदलाल बोस b) कृपाल सिंह शेखावत
   c) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा d) ए. पेरुमल
8. **राज्य बजट 2026–27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है?**
   a) 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये b) 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये
   c) 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये d) 1 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये
9. **19 मार्च 2026 को कौनसा राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया?**
   a) 77 वां b) 71 वां c) 69 वां d) 75 वां
10. **होंडा की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के किस संयंत्र से बनेगा?**
    a) नीमराना प्लांट (अलवर) b) कवाई थर्मल पावर प्लांट (बारां)
    c) टपूकड़ा संयंत्र d) पाली/नागौर प्लांट
11. **वॉर म्यूजियम की स्थापना कहां की जाएगी?**
    a) जैसलमेर b) झुंझुनूं c) बाड़मेर d) बीकानेर
12. **पद्म श्री से सम्मानित तगाराम भील किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?**
    a) सारंगी b) तबला c) अलगोजा d) संतूर
13. **कन्यादान योजना के तहत SC, ST एवं अल्पसंख्यक (BPL परिवार) को विवाह पर कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है?**
    a) 31 हजार b) 51 हजार c) 21 हजार d) 11 हजार
14. **Ziziphus mauritiana किस फल का वैज्ञानिक नाम है?**
    a) गूंदा b) खेजड़ी c) बेर d) सीताफल
15. **भारत का पहला स्वदेशी 32-बिट अंतरिक्ष-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर विक्रम-32 (Vikram-3201) को किस संस्थान में विकसित किया गया?**
    a) BEL, बेंगलुरु b) SCL, चंडीगढ़
    c) BARC, मुंबई d) CSIR-NAL, बेंगलुरु
16. **वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसने प्रदान किया?**
    a) संसद b) सर्वोच्च न्यायालय
    c) संविधान सभा d) प्रधानमंत्री
17. **राजस्थान युवा नीति 2026 कब जारी की गई?**
    a) 10 जनवरी 2026 b) 12 जनवरी 2026
    c) 15 जनवरी 2026 d) 26 जनवरी 2026
18. **गंगनहर परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया?**
    a) 1923 b) 1925 c) 1927 d) 1930
19. **राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है?**
    a) थारपारकर b) कांकरेज c) राठी d) गिर
20. **क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है?**
    a) राष्ट्रीय मरुउद्यान b) सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
    c) रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान d) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
21. **मोबाइल वेटरनरी यूनिट (MVU) के तहत पशु चिकित्सक को बुलाने के लिए किस टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं?**
    a) 1800 b) 1901 c) 1962 d) 1822

प्रश्नोत्तरी नं. – 07 के उत्तर एवं विजेताओं का नाम

उत्तर : 1(a), 2(d), 3(b), 4(a), 5(c), 6(b), 7(d), 8(c), 9(d), 10(c), 11(d), 12(b), 13(c), 14(a), 15(d), 16(b), 17(b), 18(a)

नीलम सवाई सिंह जग्गुका
जयपुर

शुभम कुमार शर्मा
कोटखावदा, जयपुर

डिम्पल तिवारी
भीण्डर, उदयपुर

राज्य सरकार की प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं तथा राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर 20 मई, 2026 तक ईमेल द्वारा **sujasconnect@gmail.com** पर प्रेषित करें। प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित प्रतिभागियों के फोटो सहित नाम एवं सही उत्तर आगामी अंक में प्रकाशित कर सम्मान स्वरूप 'राजस्थान सुजस' मासिक पत्रिका नियमित रूप से उन्हें प्रेषित की जाएगी।

नीमराणा बावड़ी

इस बावड़ी का निर्माण स्थानीय चौहान शासक राजा महा सिंह ने 1740 ईस्वी में पूरा करवाया था। यह प्राचीन जल प्रबंधन की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिसे अर्ध-शुष्क भूमि में जल संरक्षण और आपूर्ति के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन और कुशलता से निर्मित किया गया था।

पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 93 मीटर लंबाई और 22 मीटर चौड़ाई में नीमराणा बावड़ी फैली हुई है। इसमें नौ तल हैं जो प्रत्येक तल के पीछे की ओर लगभग 50 मीटर तक संकरा होते जाने के साथ धरती में समाते हुए हैं। प्रत्येक तल को छोटी खिड़कियों या छिद्रों के माध्यम से केंद्रीय कुएं से कुशलतापूर्वक जोड़ा गया है, जिससे कई स्तरों से पानी को कुशलतापूर्वक निकाला और उपयोग किया जा सकता है।

बावड़ी के सबसे ऊपरी तल में तीन तरफ बारी-बारी से बड़े और छोटे कक्ष बने हुए हैं। प्रत्येक तल पर जटिल रूप से उभरे हुए छज्जे हैं, जो छाया और स्थापत्य कला को सुंदरता प्रदान करते हैं।■

राजस्थान सुजस (मासिक)

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

पहली बार डिजिटल डेटा कैप्चर और स्व-गणना की सुविधा के साथ जनगणना-2027 आरंभ

जनगणना 2027

हमारी जनगणना, हमारा विकास

विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान जनगणना–2027 शुरू हो गया है। भारत सरकार ने जनगणना–2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की शुरुआत कर दी है। यह पूरी तरह डिजिटल डेटा कैप्चर के साथ स्व-गणना की सुविधा वाली भारत की पहली जनगणना है। प्रारंभिक चरण में स्व-गणना प्रक्रिया 8 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई , जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एवं दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र शामिल हैं।

जनगणना-2027 के डिजिटल टूल्स

- **HLBC वेब एप्लिकेशन :** उपग्रह चित्रों की सहायता से मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाकर भौगोलिक कवरेज का मानकीकरण करता है।
- **HLO मोबाइल एप्लिकेशन :** प्रगणकों के लिए ऑफलाइन ऐप, जिससे वे डेटा एकत्र कर सीधे सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं।
- **स्व-गणना (SE) पोर्टल :** उत्तरदाता स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरकर SE ID प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्रगणक सत्यापित करता है।
- **CMMS पोर्टल :** जनगणना की योजना, प्रबंधन और निगरानी के लिए केंद्रीकृत रियल-टाइम डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म।

शुभंकर 'प्रगति' और 'विकास'

जनगणना-2027 के शुभंकर 'प्रगति' (महिला प्रगणक) और 'विकास' (पुरुष प्रगणक) को मैत्रीपूर्ण और सहज प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही 'प्रगति' और 'विकास' 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में महिलाओं और पुरुषों की बराबर की भागीदारी के भी प्रतीक हैं।

राजस्थान

- **स्व-गणना (Self-Enumeration) :** अवधि-1 मई से 15 मई
- **मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (House Listing & Housing Census) :** अवधि 16 मई से 14 जून ■

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, राकेश शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - अजय कुमार, मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, जयपुर से मुद्रित (20,000 प्रतियां), 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 72 • अंक प्रतियां 1,00,000